कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

मार्गशीर्ष–पौष 2081, दिसंबर 2024

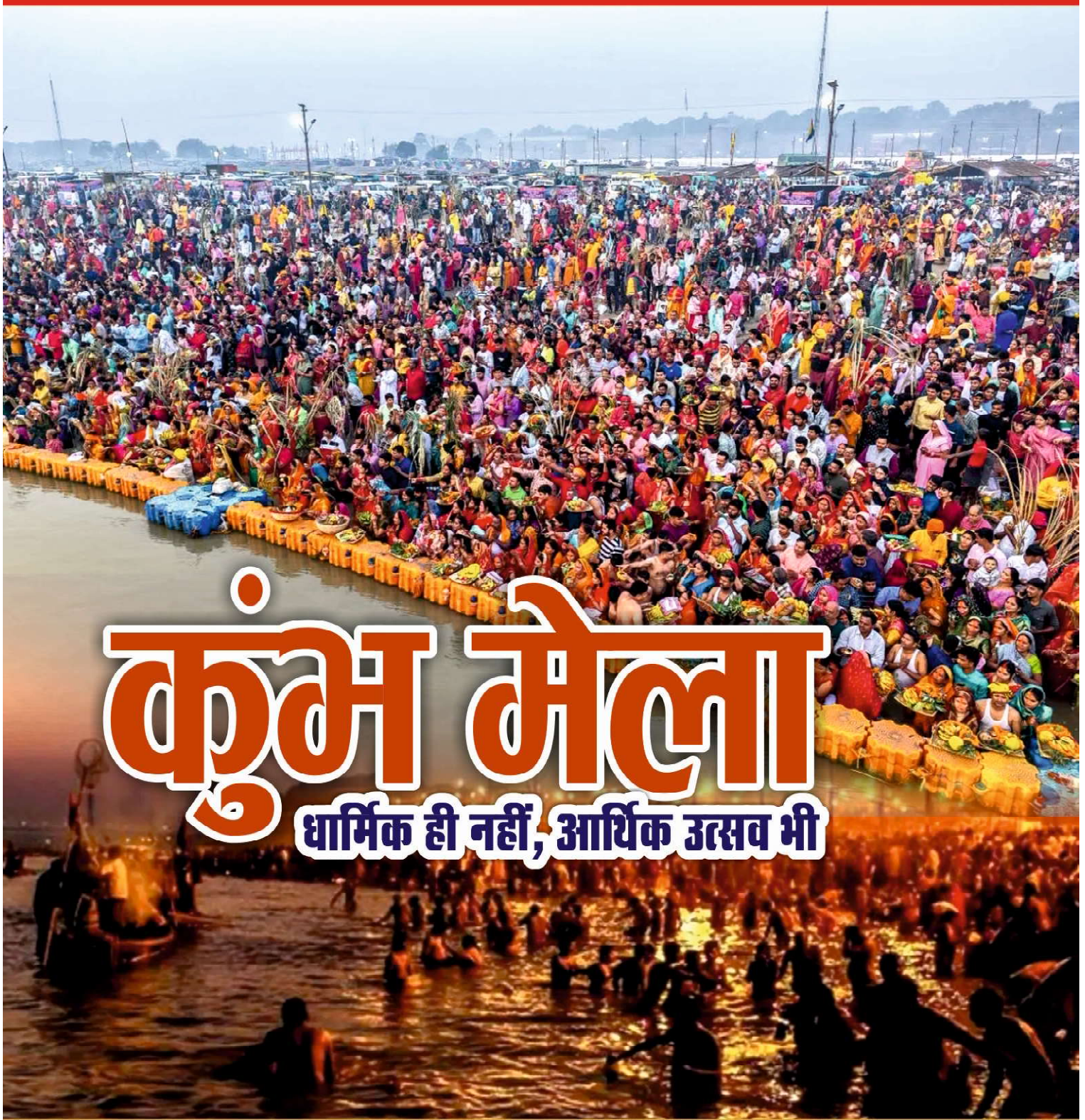

कुंभ मेला

धार्मिक ही नहीं, आर्थिक उत्सव भी

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांत सम्मेलन/बैठकें

सचित्र झलक

त्रिपुरा बैठक

प्रांत सम्मेलन, अवध

लुधियाना बैठक

नैनीताल बैठक

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–32, अंक–12
मार्गशीर्ष–पौष 2081 दिसंबर 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 36-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–06

एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिध्वनित करता है 'कुंभ'
डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 कुंभ कथा
दिखावटी आयोजन का नहीं, साझे चिंतन की जरुरत
अरूण तिवारी

10 महाकुंभ
विश्व पर्यटनः महाकुंभ से खिंच रही अर्थव्यवस्था की बड़ी लकीर
शिवानी चौहान

12 महाकुंभ
रेत पर बसाए शहर से स्थानीय विकास के खुलेंगे रास्ते
गणेश गौतम

14 महाकुंभ
महाकुंभ में फिरोजाबाद की चूड़ियां और चंबा का रुमाल भी बटोरेंगे सुर्खियां
शिवनंदन लाल

16 बैंकिंग
क्यों सही नहीं है बैंकों को विदेशियों को बेचना?
डॉ. अश्वनी महाजन

18 आजकल
डालर के मुकाबले रुपए में गिरावट की मुद्रा
अनिल तिवारी

21 विश्लेषण
मंदीः चुनौतियां और उपाय
के.के. श्रीवास्तव

24 दृष्टिकोण
भव्यता से अधिक दिव्यता का पोषक रहा है भारतीय आर्थिक दर्शन
प्रहलाद सबनानी

26 समीक्षा
भारत की आर्थिकीः दशा और दिशा
अनिल जवलेकर

28 कृषि
औद्योगिक क्षेत्र से श्रमिकों का कृषि की ओर बढ़ता रुझान
देविन्दर शर्मा

30 जलवायु
बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन
विजय गर्ग

32 खानपान
तेजी से पनप रही है डिब्बा बंद भोजन संस्कृति!
सुशील कुमार महला

पाठकनामा

विजय दिवसः पराक्रमी भारतीय सेना का साहस

भारत ने पाकिस्तानी सत्ता और सेना के अत्याचार से पीड़ित पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपना सहयोग देकर बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसका आरंभ पश्चिमी पाकिस्तान और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष के बीच 3 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्तिपूर्व हवाई हमले किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन देने के निर्णय के कारण हुआ। जिसमें पाकिस्तान को अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें भारतीय सेना द्वारा 93 हजार पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए गए और पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त होकर बांग्लादेश बन गया।

यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसीलिए देश भर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष में 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 घायल हुए। युद्ध के 8 महीने बाद अगस्त 1972 में भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता 1972 किया। इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था।

भारत की पराक्रमी सेना के साहस ने पाकिस्तान की सेना के 97,368 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। इस गौरवशाली दिवस पर स्वयं सेवकों के बल और सामर्थ्य में वृद्धि करने हेतु संघ प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को प्रहार महायज्ञ का आयोजन करता है। इस दिन स्वयंसेवकों को यह स्मरण दिलाया जाता है कि महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतना बल था कि उन्होंने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को जिरह–बख्तर, घोड़े सहित काट डाला। रानी दुर्गावती युद्ध के मैदान में घोड़े की लगाम मुँह में थाम कर दोनों हाथों में तलवार लेकर उतरी थीं और शत्रुओं को नाकों चने चबवा दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार के बल पर आदिलशाही और मुगलशाही से टक्कर लेते हुए हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की थी। हम उन्हीं महान पूर्वजों के वंशज हैं। हमारी भुजाओं में वैसा ही बल चिर स्थाई रहे, हम क्षमतावान बने रहें।

हेमेन्द्र क्षीरसागर, बालाघाट, म.प्र.

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

सरदार वल्लभभाई पटेल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि हेतु नागरिकों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

जलवायु परिवर्तन विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और भारत इस चुनौती से निपटने में सबसे आगे है।

ओम बिरला, अध्यक्ष, लोकसभा, भारत

हमें समग्र कार्बन प्रभाव को कम करने तथा स्थायित्व को अपनी सोच का केन्द्र बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव ईंधन, मल्टीमॉडल परिवहन विकल्प जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा।

पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत

हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समस्या यह है कि अपनी जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है ताकि हमारे विकास प्रयासों में कोई बाधा न आए। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम इसमें विफल रहे, तो यह निर्भरता के बोझ को बढ़ाने और हमारे विकास को धीमा करने के रूप में जनसंख्या में खतरनाक असंतुलन पैदा कर सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

चुनिंदा आयात शुल्क बढ़ाने का समय

चीन से हमारा आयात घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2018–19 में चीन से व्यापार घाटा केवल 53.6 अरब डालर रह गया, जबकि 2017–18 में यह 63 अरब डालर था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय इन आयात शुल्कों में वृद्धि का कई अर्थशास्त्रियों ने यह कहकर विरोध किया था कि इससे देश में संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलेगा और अकुशलता बढ़ेगी। यह समझना होगा कि 2018–19 में आयात शुल्कों में वृद्धि ने देश में इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकाम उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया, मोबाइल फोन के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई और वर्ष 2023–24 तक मोबाइल फोन का निर्यात 14.4 अरब डालर तक पहुंच गया। इसी तरह कई अन्य वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि देखी गई। यह पहली बार नहीं था, जब हमें टैरिफ बढ़ाने का लाभ मिला। देश में कुल विनिर्माण में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देने वाला आटोमोबाइल क्षेत्र उच्च टैरिफ के कारण ही विकसित हो सका। भारत में आटोमोबाइल उत्पादों पर 40 हजार डालर से अधिक मूल्य वाली कारों के लिए 100 प्रतिशत और 40 हजार डालर से कम मूल्य वाली कारों के लिए 60 प्रतिशत टैरिफ लगता है। आज भारत आटोमोबाइल में एक वैश्विक शक्ति है और कई भारतीय व विदेशी कंपनियां देश में कारों और अन्य आटोमोबाइल का निर्माण कर रही हैं एवं भारी मात्रा में निर्यात भी कर रही हैं। भारत से 45 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात 2023–24 में किया गया। भारत में औसत भारित टैरिफ वर्ष 2004 में यूपीए के सत्ता में आने से पहले लगभग 24 प्रतिशत था। लेकिन टैरिफ में नाटकीय रूप से कमी की गई। वर्ष 2006 तक यह लगभग छह प्रतिशत तक घटा दिया गया। इससे हमारे विनिर्माण में तबाही मच गई और आयात पर हमारी निर्भरता कई गुना बढ़ गई। टैरिफ कम करने की वकालत करने वाले अर्थशास्त्रियों की भी देश में कोई कमी नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि मुक्त व्यापार का लाभ तभी है, जब दूसरे भी इसका पालन करें, लेकिन अगर कोई देश अपने माल को भारत में डंप कर रहा हो या अन्य देश टैरिफ बढ़ा रहे हों, तो हमारा देश और अन्य देश मुक्त व्यापार के रुख को जारी नहीं रख सकते। आज अमेरिका सहित कई देश अपने उद्योगों की सुरक्षा के नाम पर टैरिफ दीवारें बढ़ा रहे हैं, परिणामस्वरूप हमारा देश पहले की तरह खुला नहीं रह सकता।

टैरिफ में चुनिंदा बढ़ोतरी का समयः वर्ष 2020 में जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नीति की घोषणा की है, तब से इंटरमीडिएट उत्पादों के आयात में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत नीति में कई क्षेत्रों को चुना गया है। इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है। इनमें एपीआइ यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, खिलौने, सौर उपकरण, अर्धचालक, वस्त्र, रसायन आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना शुरू की गई है, जिसमें सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है। लेकिन पीएलआइ योजना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों के बावजूद हमें इंटरमीडिएट्स के आयात में बहुत कमी नहीं दिख रही है। इन क्षेत्रों में घरेलू निवेश भी भारी मात्रा में हो रहा है, लेकिन चीन द्वारा डंपिंग ने पीएलआइ योजनाओं की सफलता को प्रभावित किया है। इसके अलावा, इन मध्यवर्ती उत्पादों के उपयोगकर्ता उद्योग दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के नाम पर अपने उत्पादन को जारी रखने के लिए इन मध्यवर्ती उत्पादों पर आयात शुल्क में और कमी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इन मध्यवर्ती उत्पादों पर टैरिफ कम करना जारी रखते हैं, तो हमारी चीनी आयात पर निर्भरता जारी रहेगी।

दूसरी ओर, जो निवेशक रासायनिक, एपीआइ, इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार घटक उद्योगों में निवेश कर रहे हैं, वे टैरिफ बढ़ाकर चीनी डंपिंग और अन्य अनैतिक प्रथाओं से सुरक्षा चाहते हैं। निवेशकों की मुख्य आशंका यह है कि यदि चीनी डंपिंग को नहीं रोका गया, तो उनके उद्योग फिर से बंद हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएलआइ के रूप में सरकार द्वारा दिए गए भारी समर्थन को देखते हुए, इन उद्योगों को चीनी डंपिंग से काफी हद तक सुरक्षा की आवश्यकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद, विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की उनकी चेतावनी अन्य देशों से जवाबी टैरिफ को भड़का सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका के पास यह लाभ है कि वह देश–विशिष्ट टैरिफ लगा सकता है, जो अन्य देश नहीं कर सकते। अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए विविध देशों को अपने सभी व्यापार भागीदारों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाना होगा। ऐसे में वे भागीदार भी आयात शुल्क बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे, तो भारत इस आयात शुल्क प्रतिस्पर्धा से अछूता नहीं रह सकता।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सस्ते आयात का तर्क एक अल्पकालिक घटना है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सस्ते शुल्कों के चलते चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण चीन द्वारा शोषण को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए, एपीआइ के मामले में जैसे–जैसे देश की चीनी एपीआइ पर निर्भरता बढ़ी, चीन ने एपीआइ की कीमतों में कई गुना वृद्धि करके भारतीय दवा कंपनियों और उसके माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया। यदि हम अपने व्यापार भागीदारों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो कई देशों के साथ एफटीए के अस्तित्व के कारण एक बड़ी समस्या आ सकती है, जिसके तहत हम शून्य या बहुत कम टैरिफ पर अधिकतम आयात की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे मामले में चीन या अन्य देश जिन पर टैरिफ लगाए गए हैं, वे इन देशों, जिनके साथ हमारे एफटीए हैं, उनके माध्यम से अपने निर्यात को भेजने का प्रयास कर सकते हैं। हम सख्त 'मूल देश के नियम' यानि 'रूल ऑफ़ कंट्री ऑफ़ ओरिजिन' संबंधित रोक लगाकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं।

एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिध्वनित करता है 'कुंभ'

नास्ति सत्यं सम तीर्थं नास्ति ज्ञानं सम बलम्। नास्ति धर्मम सम मित्रं नास्ति शीलं सम सुखम।।'

धर्म की बात करें, तो 'सनातन' शब्द संस्कृत की 'धृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है नित्य, शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं समय के साथ–साथ विलुप्त होती गईं परंतु सनातन धर्म और संस्कृति अपनी सहजता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और शाश्वत जीवन शैली के कारण आज भी जीवंत है, जिसका जीता–जागता उदाहरण हम अपने देश में होने वाले कुंभ और महाकुंभ के अनुष्ठानों में प्रत्यक्षतः देख–सुन और समझ सकते हैं, जहां सनातन संस्कृति आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक एकता और समरसता का अमृतोत्सव मनाती है।

महाकुंभ का उद्गम समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम हुआ था और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें चार स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। महाकुंभ देवताओं के सम्मान में आयोजित पूजन और अर्पण का भी महत्त्वपूर्ण केंद्र है। श्रद्धालु विशेष रूप से श्राद्ध (पूर्वजों को भोजन और प्रार्थना करना) और वेणी दान (गंगा में बाल चढ़ाना) जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जो समर्पण और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं।

महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंतता, प्रबुद्धता और आध्यात्मिकता का अमृतोत्सव भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक यह भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने वाला आयोजन रहा है। केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और समृद्ध भारतीय लोक संस्कृति का संगम भी है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र मिलन होता है, और वहां स्नान करना आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से न केवल पापों का प्रक्षालन होता है, बल्कि

महाकुंभ का अभूतपूर्व आयोजन भारतीयता की आत्मा और सनातन संस्कृति की दिव्यता का उत्सव है। यह हमें हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों पर गर्व करने का अवसर देता है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

पूर्वजों की आत्माओं को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों और पुराणों में उल्लिखित सूक्तों में भी इसकी महत्ता का उल्लेख मिलता है।

महाकुंभ का उद्‌गम समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है।

'गड़्गा च यमुना चैव सरस्वती च महानदी।
त्रिसोतः संगमे यत्र स्नानं मुक्ति प्रदंभवेत।।'

इसी परिप्रेक्ष्य में महाकुंभ 2025 की चर्चा समीचीन और प्रासंगिक है, जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हो रहा है। 2025 का यह महाकुंभ, न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता– संस्कृति और दर्शन का वैश्विक मंच और अद्वितीय आयोजन भी बनेगा जिसमें शाही स्नान, आरती, कल्पवास, दीप दान, प्रार्थना और अर्पण, पंचकोशी परिक्रमा इत्यादि मुख्य आकर्षण होंगे। त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला यह पवित्र समागम लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस पावन बेला में पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति न केवल सभी पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसके पूर्वजों को भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है, और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा (13 जनवरी) और मकर संक्रांति (14 जनवरी) की तिथियों पर 'शाही स्नान' या 'राजयोगी स्नान' अपना विशेष महत्त्व रखते हैं, जब संतों और उनके शिष्यों के भव्य दल स्नान करने के लिए निकलते हैं।

यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि इस विशेष स्नान के माध्यम से श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करते हैं, और संतों के प्रवचन और गहरे ज्ञान से समृद्ध होते हैं, जिससे उन्हें जीवन की गहरी आध्यात्मिकताओं का अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गंगा किनारे होने वाली आरती में दीपकों को प्रज्ज्वलित करने के साथ–साथ

प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान दीप दान का आयोजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होगा, जहां श्रद्धालु त्रिवेणी में हजारों दीपक प्रवाहित करेंगे जिसकी दिव्य और अलौकिक छटा से संपूर्ण वातावरण आलोकित और आह्लादित होगा।

मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा विधियों का अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनके लिए यह अत्यंत अविस्मरणीय अनुभव होता है, जिसमें भक्तों की इस पवित्र नदी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अहसास और भी अधिक गहराता है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान दीप दान का आयोजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होगा, जहां श्रद्धालु त्रिवेणी में हजारों दीपक प्रवाहित करेंगे जिसकी दिव्य और अलौकिक छटा से संपूर्ण वातावरण आलोकित और आह्लादित होगा। मेले की रात को नदी पर टिमटिमाते दीपकों का मनोरम दृश्य धार्मिक उत्साह और एकता की भावना से ओत–प्रोत होगा जो श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी और अमिट छाप छोड़ जाएगा।

हमेशा की तरह महाकुंभ के इस अद्वितीय आयोजन में भी कल्पवास की व्यवस्था होगी जो साधकों को आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या के साथ–साथ उच्च चेतना प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। 'कल्प' संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'ब्रह्मांडीय युग', और 'वास' का अर्थ है निवास। इस प्रकार, कल्पवास एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास की अवधि होती है, जिसमें भाग लेने वाले तीर्थयात्री सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, और सांसारिक माया–मोह तथा भौतिक सुविधाओं का त्याग कर ध्यान, प्रार्थना, वैदिक यज्ञ, होम और आध्यात्मिक प्रवचन जैसी गतिविधियों में निमग्न रहते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है।

इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को विज्ञान और धर्म के अद्‌भुत संगम का भी दृश्यावलोकन करने का मौका मिलेगा। आधुनिक तकनीकों जैसे रियल–टाइम ट्रैकिंग और वर्चुअल दर्शन इसे खास और विश्वस्तरीय आयोजन बनाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक जागरण का मंच बनेगा, बल्कि मानवता और विज्ञान के मेल का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। 2025 का महाकुंभ डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के प्रतीकों का अद्वितीय उदाहरण होगा।

'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चिद्दुः खभाग्भवेत।'

'वसुधैव कुटुम्बकम' का सार प्रस्तुत करता यह आयोजन भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रतिनिधित्व करेगा। लाखों विदेशी पर्यटक इस आयोजन में भाग लेंगे जिससे भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक सुदृढ़ता को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को एक बार पुनः पूर्णतः जीवंत और साकार करेगा। न केवल भारतीय संस्कृति की जड़ों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि इसे विश्व में और भी व्यापक पहचान दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाएगा। महाकुंभ का अभूतपूर्व आयोजन भारतीयता की आत्मा और सनातन संस्कृति की दिव्यता का उत्सव है। यह हमें हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों पर गर्व करने का अवसर देता है। ❑❑

दिखावटी आयोजन का नहीं, साझे चिंतन की जरुरत

पौराणिक संदर्भ प्रमाण हैं कि कभी नदियों की समृद्धि के काम में राजा–प्रजा–ऋषि... तीनों ही साझीदार हुआ करते थे। तीनों मिलकर नदी समृद्धि हेतु चिंतन करते थे। यही परिपाटी लंबे समय तक कुंभ की परिपाटी बनी रही। कुंभ सिर्फ स्नान का पर्व कभी नहीं रहा। अनुभव बताता है कि जब समृद्धि आती है, तो वह सदुपयोग का अनुशासन तोड़कर उपभोग का लालच भी लाती है और वैमनस्य भी। ऐसे में दूरदृष्टि और कुछ सावधान मन ही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में जीवनशक्तियों को जागृत होना पड़ता है। एकजुट होकर विमर्श करना पड़ता है। तब कहीं समाधान निकलता है। गलत काम रुक जाते हैं और अच्छे कामों का प्रवाह बह निकलता है। कुभ का यही कार्य है। यही मंतव्य!

प्रकृति का चिंतन पर्व थे कुंभ

भारतवर्ष में नदियों के उदगम् से लेकर संगम तक दिखाई देने वाले मठ, मंदिर अनायास यूं ही नहीं हैं। ऋषि, प्रकृति का प्रतिनिधि होता है। समाज ने ऋषियों को ही नदियों की पहरेदारी सौंपी थी। यह ऋषियों का ही जिम्मा था कि वे नदी किनारे आने वाले समाज को सिखाये कि नदी के साथ कैसे व्यवहार करना है। ऋषियों ने यह किया भी, तभी हमारी नदियां इतने लंबे समय तक समृद्ध बनी रहीं। लेकिन जब कभी विवाद हुआ या नदी के सम्मान में किसी ने चोट पहुंचाई, तो ऋषि ने निर्णय अकेले नहीं दिया। ऋषियों ने कहा कि नदी अकेले न समाज की है, न ऋषि की और न राजा की; नदी तो सभी की साझा है। राज–समाज–ऋषि से लेकर प्रकृति के प्रत्येक जीव व वनस्पति का इस पर साझा अधिकार है। अतः इसकी समृद्धि और पवित्रता के हक में सभी को बैठकर साझा निर्णय लेना होगा। बस! यह एक दस्तूर बन गया। राज–प्रजा–ऋषि... सभी एक निश्चित अंतराल पर नदियों के किनारे जुटने लगे। आज भी किसी न किसी बहाने भारत का समाज अपनी–अपनी नदियों

राजा हो या प्रजा.. सभी गुरू आदेश की पालना ईश्वरीय आदेश की तरह करते थे। इसीलिए कुंभ में ऋषि अपने अनुसंधानों को गुरूओं के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कल्पवासी गुरू आदेश के अनुसार ऋषि अनुसंधानों को अपने परिवार व समाज में व्यवहार में उतारते थे।

–अरूण तिवारी

के किनारे जुटता ही है; गंगापूजा, कांवडियों का श्रावणी मेला, कार्तिक पूर्णिमा, छठपूजा, मकर संक्रान्ति, पोंगल, बसंत पंचमी...। यदि कोई छेड़छाड़ न की जाये, तो भी सामान्यतः 150 सालों में नदी प्रवाह की दिशा और दशा में बदलाव आता है। छेड़छाड़ हो तो यह पहले भी हो सकता है; जैसा कि तटबंधों में फंसी उत्तर बिहार की नदी–कोसी के साथ आये साल हो रहा है। संभवतः इसीलिए 144 वर्षों में महाकुंभ का निर्णायक आयोजन तय किया गया। महाकुंभ के निर्णयों की अनुपालना और निगरानी के लिए हर छह बरस पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर कुंभ के आयोजन की परंपरा बनी।

अनुसंधान प्रसार का माध्यम थे कुंभ

कहा तो यह भी जाता है कि कालांतर में कुंभ... ऋषियों द्वारा किए गये अनुसंधानों को समाज के बीच पहुंचाने का भी एक बड़ा माध्यम बन गये थे। हमारे यहां प्रत्येक परिवार द्वारा किसी न किसी से गुरू परिवार से दीक्षा लेने की परंपरा हमेशा से रही है। प्रत्येक गुरू का शिष्य समाज उनसे मिलने कुंभ में आता था। इसे आज हम 'कल्पवास' के नाम से जानते हैं। जैसा राजा भगीरथ ने मां गंगा का वचन दिया था, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त ऐसे सज्जन कल्पवास में जुटते थे। राजा हो या प्रजा.. सभी गुरू आदेश की पालना ईश्वरीय आदेश की तरह करते थे। इसीलिए कुंभ में ऋषि अपने अनुसंधानों को गुरूओं के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कल्पवासी गुरू आदेश के अनुसार ऋषि अनुसंधानों को अपने परिवार व समाज में व्यवहार में उतारते थे।

धीरे–धीरे समाज के कलाकार, कारीगर, वैद्य आदि हुनरमंद लोग भी अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए कुंभ में आने लगे। यहां तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में आया बदलाव कुंभ को उसके असल मंतव्य से ही भटका गया।

संत समाज कभी कुंभ के दौरान समाज को निर्देशित कर एक नैतिक, अनुशासित और गौरवमयी विश्व के निर्माण का दायित्वपूर्ण कार्य करता था, उसी संत समाज के उत्तराधिकारियों ने कुंभ को महज् दिखावटी आयोजन बना दिया। आज कुंभ के दौरान लोग पवित्र नदियों में स्नान करने तथा स्नान के दौरान कचरा बहाकर नदी को और गंदा करने आते हैं, न कि नदी को समृद्ध बनाने। अब तो हमारा कुंभ, नवाचारों के प्रचार का भी माध्यम नहीं रहा। कुंभ का ऐसा मंतव्य कभी नहीं था।

दिखावटी आयोजन में बदल गये कुंभ

पता नहीं कब और कैसे कुंभ चिंतन पर्व से बदलकर सिर्फ एक स्नानपर्व बनकर रह गया? बहुत कुरेदने पर एक संत ने बताया कि कैसे 50 के दशक तक साधुओं के अखाड़ों में रोटी रूखी, लेकिन निष्ठा व सम्मान बहुत ऊंचा था। इसी दौरान प्रवचन करने वाले धर्माचार्यों के एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ, जिनके आभूषण सोने के थे, आसन चांदी के और रसोई.. छप्पन भोगों से परिपूर्ण। बावजूद इसके जब वे लंबे समय तक सम्मानित साधु समाज की अगली पंक्ति में शामिल नहीं हो सके, तो उन्होने अनैतिकता की ओर कदम बढ़ाया। रोटी सुधारने के नाम पर धीरे–धीरे उन्होंने अखाड़ों को अपने वैभव के आकर्षण में लिया। घी–चुपड़ी देकर अखाड़ों में अपने लिए सम्मान हासिल किया। हासिल सम्मान के प्रचारित करने के लिए कुंभ में दिखावे का सहारा लिया। शाही स्नान के नाम पर कुंभ अब अखाड़ों, संप्रदायों, मतों के धर्माचार्यों के वैभव प्रदर्शन का माध्यम बन गये हैं।

लिखते दुख होता है कि जो संत समाज कभी कुंभ के दौरान समाज को निर्देशित कर एक नैतिक, अनुशासित और गौरवमयी विश्व के निर्माण का दायित्वपूर्ण कार्य करता था, उसी संत समाज के उत्तराधिकारियों ने कुंभ को महज् दिखावटी आयोजन बना दिया। आज कुंभ के दौरान लोग पवित्र नदियों में स्नान करने तथा स्नान के दौरान कचरा बहाकर नदी को और गंदा करने आते हैं, न कि नदी को समृद्ध बनाने। अब तो हमारा कुंभ, नवाचारों के प्रचार का भी माध्यम नहीं रहा। कुंभ का ऐसा मंतव्य कभी नहीं था।

पुनः चिंतन पर्व बने कुंभ

आइये! कुंभ को वापस उसके मूल मंतव्य की ओर ले चलें। इसे वैचारिक चिंतन, श्रमनिष्ठा और सद्संकल्प का महापर्व बनायें। प्रकृति, समाज और विकास.. तीनों को बचायें। कुंभ गंगा रक्षा सूत्र का पालन करें; नदियों के प्रति अपना दायित्व निभायें। सुखद है कि चिंतन–मंथन को विशेष महत्व देने की दृष्टि से पूर्व में सिहंस्थ कुंभ के आयोजकों ने एक पहल की थी। उस मंथन से निकला क्या? हमने अपनाया क्या? इस पर हमें प्रयाग में होने वाले कुंभ में विचार करना होगा तथा हमारी प्राणदायिनी नदियों का अमृत जल भावी पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रहेगा, इस पर गंभीर मंथन करना होगा। अगर हमारे संत समाज, प्रशासन–शासन के लोग इस पर अमल करते है तो यह आयोजन निश्चित रूप से सार्थक होगा। ❑❑

विश्व पर्यटन

महाकुंभ से खिंच रही अर्थव्यवस्था की बड़ी लकीर

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ विश्व पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। देश प्रदेश ही नहीं सारी दुनिया के सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे 45 दिनों के कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के डुबकी लगाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए देशभर में जहां रोड शो कर रही है वहीं विदेशी लोगों को आकर्षित करने के लिए महाकुंभ में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्नेह निमंत्रण भी भेज रही है। उम्मीद है कि 2 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक महाकुंभ में भाग लेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई हासिल होने की उम्मीद है।

मालूम हो कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां अनेक धर्म, जातियाँ तथा समुदाय एक साथ निवास करते हुए एकता तथा समन्वय का भाव प्रस्तुत करते हैं। भारत में प्रत्येक धर्म से जुड़े पर्वों, त्योहारों तथा धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है क्योंकि यह समस्त भारत ही नहीं बल्कि विश्व को एक स्थान पर एकजुट करने का सामर्थ्य रखते हैं।12 वर्षों की अवधि में चार बार आयोजित होने वाला श्रद्धेय मेला, महाकुंभ इस विश्व–बंधुत्व का उत्तम उदाहरण है। कुंभ के विषय में लिखा गया है– *"गंगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे। कालसाखयोहि योगोहयं प्रोच्यते शंकरादिभिः।।"* कुंभ मेला, विश्व के सबसे बड़े समागम आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री अपने पापों को शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। वे आध्यात्मिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं तथा एक ऐसी यात्रा पर निकलने की ओर अग्रसर होते हैं जो भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को पार कराती है। परंतु वर्तमान दृष्टि में कुंभ का महत्त्व केवल धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक ही नहीं रह गया है, यह आर्थिक संवृद्धि की दृष्टि से भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

महाकुंभ मेला 2025 न केवल आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने में सक्षम है, बल्कि उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी गति देने की क्षमता रखता है।

–शिवानी चौहान

भारत के लिए पर्यटन आज एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विख्यात है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तथा सांस्कृतिक वैविध्य के साथ–साथ धार्मिक अनुष्ठानों भी वैश्विक स्तर पर पर्यटन हेतु आकर्षण का केंद्र हैं। वृंदावन हो या बनारस, चार धाम हो या अमरनाथ यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग हों या 52 शक्तिपीठ, सभी विश्वविख्यात पर्यटन स्थलों के रूप में भारत राजस्व में व्यापक योगदान करते हैं। आए दिन धार्मिक स्थलों में बढ़ती भीड़ इसकी सूचक है। हाल ही में होटल बुकिंग के लिए जानी मानी कंपनी 'ओयो' के द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2024 में मनाली, कश्मीर जैसे पर्यटन स्थलों की अपेक्षा कुर्ग, नैनीताल (कैंची धाम), बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में होटलों की बुकिंग में 28 गुना वृद्धि आई है। यह प्रमाण है कि भारत में धार्मिक पर्यटन नित–प्रतिदिन उन्नति तो कर ही रहा है, इन सभी धार्मिक स्थलों में रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनकर भी उभर रहा है।

इसी श्रंखला में महाकुंभ का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 3 वर्ष, अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष तथा महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। आखिरी महाकुंभ मेला साल 2013 में आयोजित किया गया था, इसके बाद साल 2019 में अर्ध कुंभ तथा अब वर्ष 2025 महाकुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है। कुंभ पर्व स्थल के रूप में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक भी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में उभरते हैं जहां अर्धकुंभ जैसे जैसे आयोजन भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सीआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें हवाई अड्डों और होटलों के बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल था, जबकि 2019 में कुंभ मेले से कुल 1.2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2025, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के द्वारा उत्तर प्रदेश में वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जनित किए जाने का अनुमान लगाया गया है। सीआईआई के अनुसार, चूंकि कुंभ की प्रकृति आध्यात्मिक और धार्मिक है, लेकिन इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों ने 2019 में विभिन्न क्षेत्रों में छह लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया था अतः वर्ष 2025 में राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त प्रयास कर रही है।

महाकुंभ मेला लगभग 4,000 हेक्टेयर में फैला होगा जिसमें एक अस्थायी तम्बू शहर बनाया विकसित किया जाएगा और यह अस्थायी शहर ही इस वर्ष भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार सृजन करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। महाकुंभ में भारत में दुनिया भर से 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव प्रयाग के साथ–साथ आसपास के जिलों तथा अन्य राज्यों पर पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक सभा को बढ़ावा दे रही है, उम्मीद है कि इससे आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टेम्पो संचालक, रिक्शा चालक, मंदिर स्थलों पर फूल बेचने वाले, यादगार वस्तुएं बेचने वाले, नाव संचालक और यहां तक कि होटल जैसे छोटे पैमाने के विक्रेताओं की कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगी। कुंभ मेले के आसपास के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक संवर्धन होगा। इसके साथ ही महाकुंभ के प्रयाग के अतिरिक्त वाराणसी, अयोध्या, पुरी, मथुरा विंध्यवासिनी धाम जैसे आसपास के धार्मिक स्थलों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। जिसके लिए ट्रैवल एजंसियाँ 'अयोध्या–प्रयाग–बनारस यात्रा', 'मथुरा से काशी' जैसे टूर पैकेज प्रसारित कर रही हैं। यही नहीं कुंभ के दौरान पर कुंभ स्पेशल ट्रेनों तथा बसों की संख्या अत्यधिक बढ़ाई गई है। आईआरसीटीसी के द्वारा महाकुंभ में ठहरने की व्यवस्था के लिए तीन श्रेणियों में टेंट की बुकिंग करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कुंभ में यात्री गमन की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर विज्ञापनों का संचालन कई महीनों पूर्व से आरंभ करवाया गया है जिनमें कुंभ स्नान से जुड़ी वस्तुओं तथा आवश्यक जानकारियों के विज्ञापन भी शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, "महाकुंभ डायरी, कैलेंडर, जूट बैग और स्टेशनरी जैसे महाकुंभ–थीम वाले उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। कुशल ब्रांडिंग के कारण बिक्री में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।"

इस प्रकार महाकुंभ सनातन धर्म में व्याप्त आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधि का मानव और सामाजिक उत्थान से एक मजबूत संबंध स्थापित करने का द्योतक है जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है साथ ही लाखों लोगों के लिए 'आर्थिक इंजन' के रूप उभरता है। महाकुंभ मेला 2025 न केवल आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने में सक्षम है, बल्कि उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी गति देने की क्षमता रखता है। अपने विशाल आकार और इससे पैदा होने वाली नौकरियों के साथ, इस आयोजन का उद्देश्य एक स्थायी विरासत छोड़ना है, जो भारतीय धर्म संपदा को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यह कई वर्षों तक क्षेत्र में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता रहेगा। अतः इस आयोजन का आर्थिक प्रभाव तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक एवं सीमित न होकर सार्वभौमिक होगा। ❑❑

रेत पर बसाए शहर से स्थानीय विकास के खुलेंगे रास्ते

अमृत काल के दौरान आयोजित हो रहा महाकुंभ राष्ट्रवाद की भावना से गूंजेगा। इस बार का महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की सोच का अहम प्रतीक भी होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी को विश्व स्तर का बनाने के लिए 2600 करोड रुपए का बजट जारी किया है। इस बजट से नए निर्माण, मरम्मत, भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा से जुड़ी 6000 परियोजनाओं पर दिन–रात काम किया जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन डिजिटल कुंभ और हरित कुंभ के मायने को बढ़ावा देगा। परंपरा के साथ ही तकनीक का उपयोग करके श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ में एआई और चैट बॉक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक से श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महाकुंभ में पहली बार विकसित किया जा रहा है 'चैट बाक्स कुंभ सहायक'। श्रद्धालु इसे एक दर्जन से अधिक भाषाओं में इस्तेमाल कर सकेंगे।

13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक चलने वाले प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की खबरें उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सुनाई दे रही हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हमेशा से ही संबंधित सरकारों, सनातन धर्मावलंबियों, श्रद्धालुओं और रोजगार से जुड़े लोगों को कुंभ का बेसब्री से इंतजार रहता है।

महाकुंभ का सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्ष ही महत्त्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि आर्थिक पक्ष भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। एक ऐतिहासिक उदाहरण से महाकुंभ और इसकी आर्थिकी के अंतर्संबंधों को समझा जा सकता है। 1882 में हुए महाकुंभ पर संयुक्त प्रांत के तत्कालीन सचिव ए.आर. रीड ने एक रिकॉर्ड तैयार किया था जिसमें कुंभ मेले की

2025 के महाकुंभ के बाद भी प्रयागराज में पर्यटन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार होगा।

– गणेश गौतम

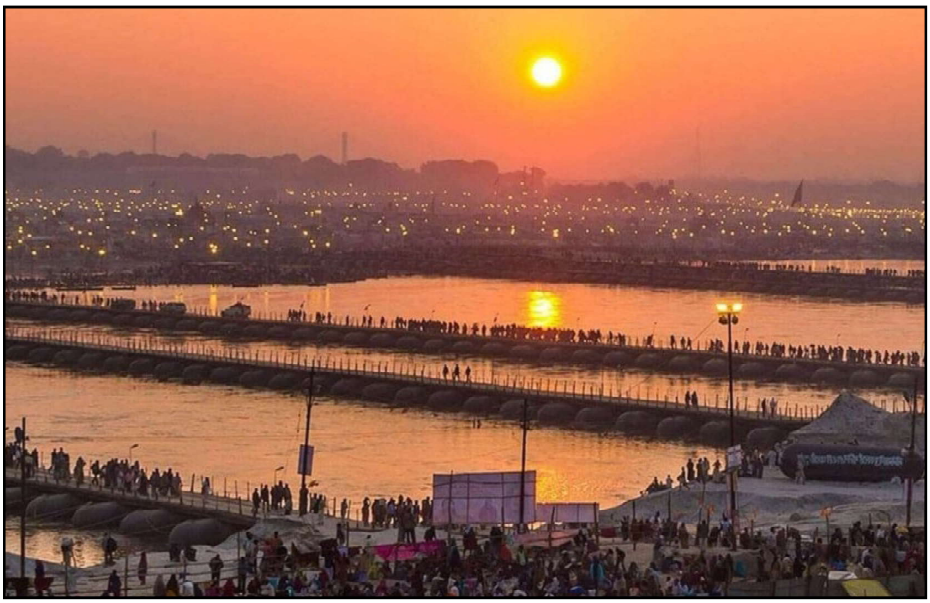

व्यवस्था और उसके लाभ का विवरण था। इस दस्तावेज में कुंभ मेले के लाभ और खर्च के बीच के संबंधों को विस्तार से बताया गया। 1882 में हुए कुंभ मेले से जुड़े आंकड़े दशति हैं कि उस समय मेले के आयोजन पर 20,228 रुपये खर्च हुए थे जबकि सरकार को कुल 49,840 रुपये प्राप्त हुए थे, अर्थात सरकार को 29,612 रुपये का लाभ हुआ, जिसका उपयोग राज्य के अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया गया। 2025 में महाकुंभ से जुड़े आर्थिक लाभ का अनुमान 25,000 करोड़ रुपये तक है।

2025 में आयोजित होने वाले प्रयाग महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6,382 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5,600 करोड़ से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए आवंटित हो चुके हैं। प्रयाग महाकुंभ के आर्थिक पक्ष की दृष्टि से पर्यटन–उद्योग में वृद्धि, स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहन, राजस्व संग्रहण, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, रोजगार सृजन आदि पहलू प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार, महाकुंभ पर चल रहे कार्य में अब तक 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। इससे न केवल प्रयागराज, बल्कि यह बनारस, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राज्य का पर्यटन विभाग मौजूदा वक्त में कई सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, जिनमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर शामिल हैं। इनकी सेवाएं महाकुंभ के दौरान दी जाएंगी। ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में चल रही है। यह राज्य की 2022 की पर्यटन नीति द्वारा पर्यटन को दिए गए प्रोत्साहन का हिस्सा है। नीति का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना और इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है।

यह पहला महाकुंभ भी होगा जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देगी। हाल में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुंभ मेला के एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने बताया, 'यह पहली बार है जब गूगल ने अस्थायी ढांचे के लिए नेविगेशन की अनुमति दी है।' यह मैप यूजर्स को मेला कैम्पस में जगहों, अखाड़ों, शिविरों और मंदिरों के जरिए नेविगेट करने की अनुमति देगा। इससे प्रशासन को तो सुविधा होगी ही, मेला घूमने आए किसी भी व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी।

2019 में 15 जनवरी से 4 मार्च तक चले प्रयागराज अर्धकुंभ के व्यवस्थित आयोजन की भी खूब चर्चा रही थी। प्रयागराज अर्धकुंभ मेले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'प्रयागराज मेला प्राधिकरण' की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यह मेले की देखरेख के लिए स्थायी निकाय है। इससे प्रयागराज मेले के महत्त्व को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का पता चलता है। 2019 के अर्धकुंभ मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। इस मेले से पहले चार चरणों में 16 सरकारी विभागों की लगभग 199 परियोजनाएं पूरी की गई थीं जिनमें गंगा नदी पर छह लेन का पुल और 275 करोड़ की लागत का चार लेन का रेलवे ओवरब्रिज शामिल था।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने मेले में दुनिया के हर देश से एक विदेशी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था। इनमें वरिष्ठ राजनेता, समाज सुधारक, योग चिकित्सक, शिक्षाविद, कलाकार, वरिष्ठ नौकरशाह, चिकित्सा पेशेवर वगैरह शामिल थे। 70 से ज्यादा देशों के राजनयिकों ने मेले की तैयारियों को देखा–परखा था। उन्होंने कम समय में रेत पर शहर बसाने और मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर आश्चर्य जताया था। इस मेले की सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था और आयोजन का संज्ञान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस द्वारा भी लिया गया था।

आर्थिक रूप से कुंभ मेला 2025 से स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन को अप्रत्याशित बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लाखों तीर्थयात्रियों के आने से आतिथ्य, परिवहन और स्थानीय बाजार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।" विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को काफी लाभ होगा जिससे क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। प्रयागराज और आसपास से जुड़े हर स्थल का विकास कार्य जोरों पर है। इन विकास कार्यों में बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन, रोजगार सृजन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा शामिल हैं।

महाकुंभ केवल समय– सीमित आयोजन नहीं है; इसके दीर्घकालिक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम हैं, जो देश की सॉफ्टपॉवर को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ के आयोजन से जो बुनियादी ढांचा और सुविधाएं बनती हैं, वे भविष्य में प्रयागराज और आसपास के इलाकों के लिए विकास के रास्ते खोलती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, महाकुंभ के कारण प्रयागराज में पर्यटन उद्योग में लगातार वृद्धि हो रही है, और यह शहर प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। 2025 के महाकुंभ के बाद भी प्रयागराज में पर्यटन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार होगा। ❑❑

महाकुंभ में फिरोजाबाद की चूड़ियां और चंबा का रुमाल भी बटोरेंगे सुर्खियां

आस्था की जड़े विश्वास पर टिकी होती है। जिस मकर संक्रांति को माघ मेला शुरू होता है, उसका आधार ग्रह और नक्षत्र की गणना है और इस विद्या का विकास ऋग्वेद से भी हजारों साल पहले कृषि के जन्म से जुड़ा हुआ है। कृषि के पर्व के रूप में भारत की बौद्धिक सांस्कृतिक संबद्धता दिखाई देती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति खिचड़ी के रूप में मनाई जाती है, दक्षिण में ओणम के रूप में। पूर्वोत्तर में बिहू के तौर पर जबकि पंजाब में बैसाखी के रूप में। माघ में संगम स्नान का महत्व काल गणना के साथ–साथ आस्था के रूप में बद्धमूल हो गया है। इसलिए कृषि संस्कृति, नक्षत्र गणना और आस्था का समन्वय कुंभ की अवधारणा में विद्यमान है।

चीनी यात्री ह्वैन सॉन्ग के यात्रा विवरण के अनुसार भारत के तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन माघ मास में प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म सभा में अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे। नवीं सदी मेंआदि गुरु शंकराचार्य ने पूरी, द्वारिका, श्रृंगेरी एवं बद्रीनाथ में चार मठों की स्थापना करने के पश्चात लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले की परंपरा शुरू की थी। एशियाटिक रिसर्च के छठवें खंड में कुंभ मेले का वर्णन है। वर्ष 1398 के ऐतिहासिक दस्तावेज में हरिद्वार कुंभ मेले का वर्णन है जिसमें विदेशी आक्रांता तैमूर लंग ने भारी तबाही मचाई थी।

वर्ष 1915 में हरिद्वार महाकुंभ के अवसर पर स्वामी श्रद्धानंद के साथ महात्मा गांधी भी सम्मिलित हुए थे।महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में हरिद्वार के कुंभ पर्व का वर्णन करते हुए लिखा था, मैं यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थ क्षेत्र में पवित्रता के शोध में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा,किंतु कुंभ पर्व में स्नान को जूटे 17 लाख लोगों को देखना मुझे बेहद विस्मयकारी लगा। इतना तो तय है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पाखंडी तो कदापि नहीं हो सकते। इस तरह की श्रद्धा मनुष्य की आत्मा को

योगी सरकार द्वारा देश–विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों को कुंभ आधारित सोविनियर गिफ्ट किए जाएंगे। इसमें भी प्रदेश के हस्तशिल्प और ओडीओपी को प्राथमिकता दी जाएगी।
–शिवनंदन लाल

किस हद तक ऊपर उठाती होगी यह कहना बेहद कठिन है।

कुंभ जैसे आयोजनों में देश की विविधता अनेक रूपों में साकार होती है। एक ओर साधु सन्यासी, मठ मंदिर, अखाड़े के धार्मिक प्रतिनिधि, धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले संगठन होंगे तो दूसरी ओर लाखों कल्पवासी, देश भर के तीर्थ यात्री, विदेशी पर्यटक होंगे। तीसरी ओर नजर डालें तो मेले में अपनी दुकान लगाने वाले छोटे बड़े व्यापारी, प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र खोलने वाली सरकारी अर्द्ध सरकारी संस्थाएं होगी तो चौथी तरफ रामलीला, रासलीला, नौटंकी आदि के माध्यम से सामान्य तीर्थ यात्रियों का मनोरंजन करने वाली मंडलियां भी होगी। कहने का आशय यह की विविधता विभिन्न रूपों में प्रकट होगी।

प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की भव्यता, दिव्यता और नव्यता को देखते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर संगम किनारे इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत देश दुनिया के लोग विभिन्न राज्यों विशेष कर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की शिल्प कला से परिचित हो सकेंगे।

महाकुंभ में पहली बार होने जा रहा टॉप 100 हस्तशिल्पियों का संगम, जिसमें देश की सबसे कीमती कलाकृतियां प्रस्तुत होगी। डबल इंजन की सरकार के प्रयास से दुनिया देखेगी बनारसी साड़ियों से लेकर दक्षिण भारतीय मूर्ति कला का अद्भुत प्रदर्शन। सीएम योगी के प्रयास से 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' बनेंगे आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज के मूंज से बने उत्पादों को भी देख और खरीद सकेंगे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार डबल इंजन की सरकार देश की सबसे कीमती कलाकृतियों को प्रस्तुत करने जा रही है। इस प्रदर्शनी का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट किए जाने की भी तैयारी है। संगम तीरे लगने वाली प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी से लेकर प्रमुख दक्षिण भारतीय कलाकृतियों को शोकेस किया जाएगा। इसमें प्रयागराज के मूंज से बने उत्पाद विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होंगे।

विभिन्न राज्यों की कला का अद्भुत संगम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत इस बार महाकुंभ को अद्भुत और आलौकिक बनाने की तैयारी चल रही है। सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, प्रयागराज तान्या बनर्जी ने बताया कि महाकुंभ में देश–दुनिया के 45 करोड़ लोगों के सामने भारत के 100 प्रमुख शिल्पियों के बेहतरीन उम्दा कार्यों का प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।

हस्तशिल्प उत्पाद के लिए वेबसाइट

महाकुंभ के दौरान लाइव प्रदर्शनी में देश भर के शिल्पकारों की बनाई हुई कलाकृतियों की खरीद–बिक्री भी की जाएगी। इसके लिए बाकायदा अपनी वेबसाइट डेवलप की गई है। यह इंडिया हैंड मेड वेबसाइट दुनिया की बड़ी–बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियों को टक्कर दे रही है। भारत ही नहीं, देश–विदेश के लोग भी इस वेबसाइट पर जाकर हस्तशिल्प के सामान की खरीद–बिक्री कर सकते हैं।

बनारस का सॉफ्ट स्टोन और जम्मू कश्मीर की पशमीना शॉल

महाकुंभ के दौरान हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में बनारस के सॉफ्ट स्टोन से लेकर जम्मू–कश्मीर की पशमीना शाल तक उपलब्ध रहेगा। प्रयागराज के मूंज क्राफ्ट, बांदा के सजर पत्थर, महोबा के गौरा पत्थर, झांसी के सॉफ्ट खिलौने,मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियां और काशी की बनारसी साड़ियां भी लोगों को आकर्षित करेंगी।

महाकुंभ के दौरान हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी के तहत महिलाओं की पसंद का भी विशेष ख्याल रखा गया है।

फिरोजाबादी चूड़ियां और चंबा रूमाल

महाकुंभ के दौरान हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी के तहत महिलाओं की पसंद का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसके तहत फिरोजाबाद की चूड़ियां और कांच के बर्तन से लेकर हिमाचल प्रदेश की विशेष कढ़ाई वाला चंबा रूमाल भी रहेगा। गोरखपुर के टेराकोटा, निजामाबाद आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन, बलिया की बाली और टिकुली, भदोही की कालीन, सहारनपुर में सींग के सजावटी आइटम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ऊनी वस्त्र, पंजाब के फुलकारी और राजस्थानी जूते के अलावा बरेली के बांस की कलाकृतियां और मुरादाबाद के पीतल के सामान विशेष आकर्षण रहेंगे।

लकड़ी के खिलौने लुभाएंगे

महाकुंभ में ओडीओपी के तहत हाथी के अंदर हाथी और ऐसे ही एक–एक करके उसकी आंठ लेयर बना कर कलाकृति की प्रदर्शनी की जाएगी। चित्रकूट और काशी के प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने भी विशेष तौर पर लुभाएंगे।

विशिष्ट अतिथियों के लिए सोविनियर

योगी सरकार द्वारा देश–विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों को कुंभ आधारित सोविनियर गिफ्ट किए जाएंगे। इसमें भी प्रदेश के हस्तशिल्प और ओडीओपी को प्राथमिकता दी जाएगी। हस्तशिल्प की कई कलाकृतियों को भी इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। ❑❑

क्यों सही नहीं है बैंकों को विदेशियों को बेचना?

वर्ष 2020 के मार्च माह में भारत के एक महत्वपूर्ण निजी बैंक, यस बैंक के निजी प्रबंधन की गलतियों (भ्रष्टाचार सहित) के कारण लगभग दिवालिया हो गया था। लोगों का विश्वास खोने के बाद बैंक से जमा कर्ताओं ने अपनी राशि वापिस लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते बैंक को अपने लेनदेन को रोकना पड़ा। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (एक सरकारी बैंक) ने 49 प्रतिशत शेयर ख़रीद कर उसे अपने हाथ में लिया, जिससे यस बैंक में जमा कर्ताओं का विश्वास पुनः जम गया। उसके बाद यह बैंक पुनः उठ खड़ा हुआ और अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हो गया। बाद में यस बैंक ने नये शेयर जारी कर और पूँजी जुटाई, और भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत तक आ गयी। स्टेट बैंक के अलावा 11 अन्य ऋणदाता संस्थाएँ हैं जिनके पास यस बैंक के लगभग 9.74 प्रतिशत शेयर हैं। यस बैंक के 16.05 प्रतिशत शेयर अन्य दो निजी इक्विटी फंडों के पास हैं।

समाचार पत्रों की हालिया रपटों के अनुसार जापान की मितसुभिषी यूएफजे फाइनेंसिएल ग्रुप नामक कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यस बैंक में शेयरों को बेचने की बात आगे बढ़ गई है। प्रस्तावित विदेशी निवेशक, यस बैंक के 51 प्रतिशत शेयर क़ब्ज़ाना चाहते हैं ताकि उसके पास निर्णय का अधिकार आ जाये। इस के लिए हालाँकि वे पहले तो भारतीय रिज़र्व बैंक की इस नियमानुसार शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें अगले 15 वर्षों में अपनी प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को 26 प्रतिशत तक लाना होगा, लेकिन अब वे वो भी मान गये हैं।

गौरतलब है कि इस बैंक को उबारने में भारतीय स्टेट बैंक ने 7520 करोड़ रूपए का पुनः पूंजीकरण किया था। लेकिन बैंक के पुनरूद्धार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई पूंजी बढ़कर अब 18000 करोड़ रूपए पहुंच चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद न केवल जमा कर्ताओं का पैसा डूबने से बच गया, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हुआ और इस प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक को भी 10000 करोड़ रूपए से अधिक का पूंजीगत लाभ भी हुआ। ऐसे में इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या यस बैंक के 51 प्रतिशत शेयरों को विदेशी हाथों में सौंप कर, यानी यस बैंक जैसे महत्वपूर्ण बैंक को विदेशी हाथों में सौंपना उचित होगा।

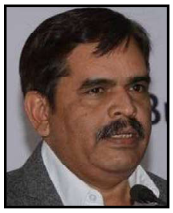

दुनिया के कोई भी महत्वपूर्ण देश आमतौर पर पिछले दरवाजे से अपने बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह के प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं।
– डॉ. अश्वनी महाजन

एलपीजी नीतियों के अंतर्गत कई सरकारी उद्यमों का निजीकरण किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में चूंकि पहले से ही निजी भारतीय और विदेशी बैंक कार्यरत थे और वे बदस्तूर चलते रहे। इसके साथ ही साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ गैर वित्तीय संस्थानों को बैंकों में बदला गया और कुछ नए बैंकों को निजी क्षेत्र में काम करने के लाईसेंस प्रदान किए गए। लेकिन इस दौरान भी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण से सरकार बचती रही।

गौरतलब है कि बैंकिंग किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र है। यह बात सही है कि दुनिया में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। अमरीका और यूरोप सरीखे पूंजीवादी देशों में ज्यादातर बैंक निजी हाथों में हैं। निजी बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि बीमा की सीमा तक ही सुरक्षित होती है। बीते सालों में अमरीका में ही हजारों बैंक दिवालिया हुए, जिसके चलते जमाकर्ताओं को उनकी गाढ़े–पसीने की कमाई से हाथ धोना पड़ा। यूरोप की स्थिति भी बहुत भिन्न नहीं है और वहां भी आए दिन बैंकों की दिवालिया होने की खबरें आम बात है।

भारत एक ऐसा देश है, जहां आजादी के बाद और खासतौर पर 1969 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद निजी बैंकों के दिवालिया होने की भी खबरें अपवाद हैं। सार्वजनिक बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि डूबना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि इस राशि की सरकार की संप्रभु गारंटी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त नियमन के कारण निजी बैंकों में लोगों की धन राशि काफी हद तक सुरक्षित है और जब कभी कुप्रबंधन के कारण उनके दिवालिया होने की संभावना भी बनती है तो सरकारी हस्तक्षेप से उसे दुरूस्त कर दिया जाता है। पिछले दिनों यस बैंक का पुनरूद्धार उसका का जीता–जागता एक उदाहरण है।

बैंकों का निजीकरण उन्हें विदेशी हाथों में सौंप कर ही क्यों?

हाल ही में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या को कुछ कम किया गया है। साथ ही साथ समय–समय पर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण की बात को दोहराती भी रही है। लेकिन अभी तक किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निजीकरण नहीं किया गया है।

आज जब देश में इस विषय पर नीतिगत चर्चा के बिना एक महत्वपूर्ण बैंक जो, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिग्रहीत कर डूबने से बचाया गया था, को विदेशी हाथों में सौंपना यस बैंक के ग्राहकों, देश के वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए उपयुक्त होगा। क्या यस बैंक को विदेशी हाथों में सौंपना, एकमात्र विकल्प है, या उसके अलावा भी विकल्प हैं? यदि विकल्प हैं तो उनपर गंभीरता से विचार हुआ है या नहीं?

क्या रणनीतिक विनिवेश ही एकमात्र विकल्प है?

जब सरकार रणनीतिक निवेशकों की तलाश में विनिवेश के साथ आगे बढ़ रही थी, तो कुछ हलकों से एक समझदारी भरा विचार आया कि क्या हम इक्विटी रूट के ज़रिए विनिवेश नहीं कर सकते और तब से सरकार विभिन्न वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकार द्वारा रखे गए शेयरों को बाज़ार में बेचकर इक्विटी रूट के ज़रिए विनिवेश कर रही है। इस प्रक्रिया में, सरकार विभिन्न वाणिज्यिक उपक्रमों में अपनी इक्विटी को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है और अपने विकास संबंधी व्यय को निधि देने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि भी जुटा सकती है

वर्तमान मामले में, जबकि एसबीआई यस बैंक में अपने निवेश की वसूली करने के लिए इच्छुक हो सकता है, शेयर बाज़ार में बैंक में एसबीआई की शेयरधारिता को विनिवेश करके भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक को उतनी ही राशि मिलेगी जितनी उसे किसी विदेशी फ़र्म को अपनी हिस्सेदारी बेचकर मिलने की उम्मीद है। यदि बाज़ार में बेचे जाने वाले शेयर आम जनता के पास हैं, तो विविध शेयरधारिता यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में किसी विदेशी खिलाड़ी का दबदबा नहीं रहेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से एसबीआई ने यस बैंक को बचाया है, तब से लोगों का यस बैंक पर भरोसा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि वे यस बैंक में अपनी जमा राशि को एसबीआई में जमा राशि के बराबर मानते हैं, जिस पर वास्तव में संप्रभु गारंटी है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक हिस्सा यह है कि एसबीआई सहित विभिन्न निवेशकों द्वारा यस बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के संबंध में बंद दरवाजे की बैठकों में क्या हो रहा है, इसके बारे में जमाकर्ताओं को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है। निष्पक्षता से, जमाकर्ताओं को बताया जाना चाहिए कि वे अब एसबीआई के संरक्षण और इसलिए संप्रभु संरक्षण का आनंद नहीं ले पाएंगे।

तीसरा, दार्शनिक मुद्दा यह है कि क्या हमें बैंकिंग प्रणाली में लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहिए। यदि यस बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी विदेशियों को बेचने का प्रस्तावित सौदा हो जाता है, तो इससे बैंकों के विनिवेश और उन्हें विदेशियों को बेचने का एक बड़ा मामला खुल सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान परिदृश्य में, हमारे पास ऐसे बहुत से भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं जो भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी खरीद सकें, जबकि विदेशी खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। यदि इक्विटी मार्ग से विनिवेश की संभावना को खारिज कर दिया जाता है, तो विदेशी संस्थानों की बाढ़ आ सकती है, जो 'सरकार का व्यवसाय में कोई काम नहीं है' के दर्शन के तहत हमारे अच्छे से चलने वाले बैंकों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हैं।

इसलिए, एसबीआई और अन्य निवेशकों को इक्विटी रूट के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रेरित करना और भारतीय प्रबंधन को यस बैंक चलाने देना उचित होगा। विदेशी खरीदार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मुफ्त प्रवेश के लिए कोई मूल्य (पूंजी की एक छोटी राशि के अलावा जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है) नहीं ला रहा है। दुनिया के कोई भी महत्वपूर्ण देश आमतौर पर पिछले दरवाजे से अपने बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह के प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। ❑❑

डालर के मुकाबले रुपए में गिरावट की मुद्रा

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीसरी कारोबारी सत्र में कमजोर रहा और लगातार गिरते हुए 85.27 (अस्थाई) प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपए को लेकर धारणा कमजोर हुई है। विदेशी मुद्रा कारोबार के जानकारों का मानना है कि आयातकों की ओर से डॉलर की मांग में वृद्धि तथा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा आक्रामक आयात शुल्क लगाने की आशंका से अमेरिकी मुद्रा डॉलर में तेजी आई है फलतः रूपया नीचे की ओर जा रहा है।

19वीं सदी के आखिर में अपने प्रसिद्ध नाटक 'दी इंर्पोटेंस आफ बीइंग अर्नेस्ट' में ऑस्कर वाइल्ड ने भारतीय रुपए के मुंह के बल गिरने का जिक्र किया था। खेद का विषय है कि उसके एक सदी से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी रूपए के मूल्य की ताजा तरीन गिरावट कमोवेश वैसी ही है जैसी वाइल्ड के जमाने में रही होगी। 24 दिसंबर 2024 को बाजार में एक डालर का मूल्य और 12 पैसे लुढ़ककर 85.27 रुपए हो गया। यह सर्वकालिक निचला स्तर है। इससे पहले 12 जुलाई 2011 को विनिमय बाजार में एक डालर का मूल्य 44 रूपये था। अगस्त 2013 में यह विनिमय मूल्य 63 रुपए का था। 6 दिसंबर 2021 को रुपए और डॉलर का विनिमय दर 75.30 रुपए प्रति डॉलर थी जो 25 अप्रैल 2022 को और गिरकर 76.74 और 12 जून 2022 को 78.20 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गई।

रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपनी नीतियों में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है। कोरोना के बाद दुनिया के तमाम देश मंदी की चपेट में आ गए थे। उस महामारी से उबरने के लिए सभी ने अपने–अपने तरीके से उपाय किए। अमेरिकी फेडरल ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कर उसे 4.3 प्रतिशत पर ला दिया है। इस तरह डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है। फिर जब से राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है निवेशकों को लगने लगा है कि वहां निवेश

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बड़े और सधे हुए आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर है कि तब रूपया भी उठेगा और देश का नाम बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार होगा।

–अनिल तिवारी

करना सबसे अधिक फायदेमंद है। इसलिए बहुत सारे निवेशकों ने भारत से अपने पैसे निकालकर अमेरिका का रुख कर लिया है। इस कारण विदेशी मुद्रा भंडार में छीजन दर्ज होनी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट लगभग रुकी हुई थी। दो साल पहले तो रूपया धीरे–धीरे ऊपर की ओर बढ़ने भी लगा था। तब विशेषज्ञों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की निकासी करके रुपए की कीमत को रोक रही है। अगर विशेषज्ञों की बात सही है तो फिर अप्रत्याशित गिरावट कैसे और क्यों हो रही है? संभव है कि अब वह तरीका शायद काम नहीं आ रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट का असर बाजार, पर्यटन, शिक्षा आदि पर सीधे और अधिक पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकतर ईंधन, तेल दूसरे देशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो सरकार का खर्च बढ़ जाता है। इसके अलावा दवाइयों के लिए कच्चा माल, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक साजो–सामान आदि के लिए भी भारत अन्य दूसरे देशों पर निर्भर है। विदेश पढ़ने गए विद्यार्थियों और पर्यटकों की जेब पर भी बोझ बढ़ जाता है। इसलिए भी रुपए की कीमत का गिरना चिंताजनक होता है। रुपए की कीमत गिरने की कुछ वजह शीशे की तरह साफ है। व्यापार घाटा बढ़ता है तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट जाती है। हालांकि वर्षों से निर्यात बढ़ाने पर सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहे हैं। घरेलू बाजार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर हर संभव कोशिश की जा रही है। मगर हकीकत यह है कि निर्यात में लगातार कमी देखी जा रही है। व्यापार घाटा पाटने के लिए कई एक विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने और देसी स्वदेशी वस्तुओं को प्रश्रय देने की कोशिश की गई, इसका कुछ असर भी कई एक क्षेत्र में देखने को मिला लेकिन फिर भी हमारा व्यापार घाटा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खासकर चीन के साथ घाटे का आंकड़ा आसमान छू रहा है।

महंगाई पर काबू पाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो रेट को ऊंचा बनाए रखा है लेकिन स्थिति यह है कि बाजार में पूंजी का अपेक्षित प्रवाह नहीं बन पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। इन स्थितियों का असर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पड़ता है। जैसे ही बाहरी निवेशकों को यह लगने लगता है कि किसी देश में उपभोक्ता व्यय घट रहा है तो वे उस देश में निवेश करने से बचते हैं। पिछले कुछ समय से हमारी विकास दर और उसमें भी विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है, बल्कि कहे तो नकारात्मक की ओर जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि डॉलर की आवाक कम हुई है। इस स्थिति में रुपए की कीमत में गिरावट लाजमी है। रुपए की कीमत गिर भी रही है। इससे उत्पन्न होने वाले संकटों और अर्थव्यवस्था के संचालन को लेकर चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। प्रश्न यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड डालर तक ले जाने को संकल्पित है मगर रुपए की गिरावट का रुख देखते हुए इस पर आसानी से भरोसा नहीं बन पाता। ऐसे में एक प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में रुपए का धीरे–धीरे अवमूल्यन संभव है अथवा रुपए को मजबूत करने की रणनीति बनाना असंभव है? पिछले काफी समय से सरकारों द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई है और यह प्रयास हुआ है कि कम से कम

महंगाई पर काबू पाने के मकसद से रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो रेट को ऊंचा बनाए रखा है लेकिन स्थिति यह है कि बाजार में पूंजी का अपेक्षित प्रवाह नहीं बन पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है।

आयात शुल्कों पर आयात की अनुमति दी जाए। चीन समेत कई देशों द्वारा आयातों की भारी मात्रा में डंपिंग के चलते हमारे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आयातों पर हमारी निर्भरता बढ़ गई। इसके साथ ही हमारा व्यापार घाटा बढ़ता गया जिसका सीधा असर डॉलर की मांग पर पड़ा और रुपए का अवमूल्यन होता गया।

ऐसे में क्या करें कि रूपया संभले

यह बात ठीक है कि बढ़ती तेल कीमतों और उसके कारण बढ़ते भुगतान घाटे पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमरीकी प्रशासन द्वारा की अपनी खुद की नीतियों पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से विदेशी संस्थागत निवेशकों के बहिर्गमन पर भी भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अनुशासित करते हुए उनके बहिर्गमन को रोकने के लिए यथोचित उपाय/प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा सकते हैं।

मालूम हो कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने लाभों पर कोई कर देना नहीं पड़ता इसलिए वे कभी भी रातों–रात अपना निवेश लेकर बिना किसी

को बताए बाहर लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार के निवेशकों पर लॉक इन पीरियड की शर्त लगाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। **स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन** इस विषय को लेकर लगातार सरकार से मंत्रणा करते रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है तो यह शर्त लगाई जा सकती है कि यदि कोई विदेशी निवेशक भारत में आता है तो एक निश्चित समय काल के लिए वह निवेश करके रखें। अगर किन्हीं परिस्थितियों में वह अपना निवेश बाहर ले जाना चाहता है तो सरकार को सूचित करें ताकि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। ज्ञात हो कि कई देशों में संस्थागत निवेशकों द्वारा अपना धन बाहर ले जाने पर 'कर' भी लगाया जाता है, जिसे 'टॉबिन टैक्स' के नाम से जाना जाता है। इस तरह के कर का प्रावधान करके सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों के बहिर्गमन को बहुत हद तक काबू कर सकती है। इसमें शक नहीं की रुपए की मौजूदा मुसीबत में अंतरराष्ट्रीय कारक भी काम कर रहे हैं। भारतीय स्थिति से जुड़े यह कारक विश्व अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचागत विशेष के ऊपर से असर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमें यह समझना होगा कि लगातार बहुत भारी चालू खाता बनाए रखने के बावजूद अमेरिकी डॉलर की स्थिति पुख्ता बनी हुई है जबकि भारतीय रूपया मौजूद घाटे के सामने बैठता जा रहा है।

रुपया आज जिस तरह से नीचे जा रहा है उसे तरह से इसे नीचे नहीं जाने दिया जा सकता है। क्योंकि आयातों पर बढ़े कर्ज का बोझ अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है इससे जनता पर मुद्रा स्थिति का दबाव बढ़ता है।

कुल मिलाकर बड़े हुए आयात के चलते विदेशी मुद्रा का भुगतान बड़ा है लेकिन इसमें संतुलन लाने के लिए निर्यात के मोर्चे पर हमें पीछे है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने की वजह से निवेश पर असर पड़ा है जिसके चलते रोजगार के नए मौके बनने के बजाय छंटनी प्रक्रिया तेज हुई है। लेकिन इसके समानांतर का सच यह है कि संकट उतना बड़ा नहीं है जिससे कि उबरा न जा सके। अगर उपायों को खांचे से बांटने के बजाए उसे समग्रता में और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। इसके लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और निजी उद्योगों को मिलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में पहल करनी होगी। छोटे–मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बड़े और सधे हुए आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर है कि तब रूपया भी उठेगा और देश का नाम बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार होगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

मंदीः चुनौतियां और उपाय

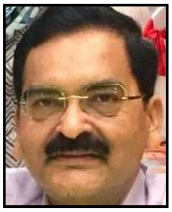

इन दिनों विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के अंदेशे में है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी साल 2024 कठिन और मुश्किल भरा रहा है। विकास की राह में सबसे ज्यादा अड़चन महंगाई ने पैदा की। आर्थिक विकास की कहानी में मंदी आई है, लेकिन देश की दीर्घकालीन क्षमता बरकरार है। राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक नीति समायोजन और संरचनात्मक सुधारों के सचेत प्रयास से भारत न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों से निपट सकता है, बल्कि अपेक्षित विकास की कहानी फिर से पटरी पर आ सकती है।

– के.के श्रीवास्तव

वर्ष 2024 के प्रथम तीन तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो देश की दीर्घकालीन विकास संभावनाओं के बारे में सरकार के आश्वासन के बावजूद चिंता का विषय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत तक पहुंचाने की उम्मीद है, जो कि संभावित रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान कायम रख सकती है। हालांकि विकास की यह दर रोजगार सृजन, आय असमानता और सतत् विकास जैसी भारी दबाव वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने उच्च विकास चरणों में लगातार 8 प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल किया है। विकास की ऊंची दरों के कारण वहां मजबूत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, आय की असमानता पर बहुत हद तक काबू पाया गया और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारत की मौजूदा विकास दर के साथ इन मोर्चों पर उस तरह के नतीजे देने के लिए उत्साह कम ही दिखा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मंदी अस्थाई अथवा चक्रीय है? या यह कोरोना महामारी के उपरांत कम आधार संसाधनों द्वारा संचालित होने के बावजूद प्राप्त सुधार के बाद महामारी पूर्व के रुझानों की वापसी के संकेत है? ऐसे में अहम बात यह है कि किसी भी रूप में मौजूदा मंदी अनुमान से कहीं अधिक गंभीर है और इस पर शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

मंदी के मुख्य कारक

वर्तमान में निर्माण, विनिर्माण, बिजली और उपयोगिताएं जैसे द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहे हैं। स्वस्थ कॉर्पोरेट के समृद्ध बैंकिंग तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के बावजूद निजी पूंजीगत व्यय स्थिर हो गया है। पशु आत्माओं की कमी या भविष्य में मजबूत मांग की प्रत्याशा में निवेश की इच्छा ने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया है। निवेश करने के लिए व्यवसायों के बीच उभरी हिचकिचाहट ने उपभोक्ता मांग को कम कर दिया है,

जिससे आर्थिक विकास में सीधे तौर पर बाधा आ रही है। वित्तमंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित प्रमुख नीति निर्माताओं ने उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव पर मुद्रास्फीति संबंधी चिताओं का हवाला देते हुए सदैव अपनी ओर से सावधानी बरत रहा है। यह ठीक है कि असुरक्षित गैर बैंक ऋण पर सख्त नियमों के चलते उपभोक्ता खर्च और अधिक संकुचित हुआ है। ऐसे में ब्याज दरों को कम करने से अस्थाई बढ़ावा मिल सकता है लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता की कीमत पर विकास को प्राथमिकता देना जोखिम पैदा करना है। साथ ही राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता विकास प्रोत्साहन के रूप में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की गुंजाइश को कम करती है।

धीमी वृद्धि ने दीर्घकालिक निहितार्थ

कोरोना महामारी के बाद सुधारात्मक चरण के दौरान भारत ने अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में लचीलापन दिखाया है। हालांकि देश के 150 करोड़ नागरिकों के लिए एक सभ्य जीवन मुहैया कराने हेतु 7 प्रतिशत की न्यूनतम विकास दर को बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में भारत का जनसांख्यिकीय के लाभांश लगातार कम हो रहा है, क्योंकि कम उपयोग की गई युवा क्षमता और समग्र जनसंख्या में उनकी घटती हिस्सेदारी इसका प्रमुख कारण है।

हाल के दिनों में खड़े हुए भू–राजनीतिक तनावों और व्यापार युद्ध के पार्श्व में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भारत की चुनौतियों को और बढ़ा रही है। वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख खिलाड़ी चीन अति क्षमता से जूझ रहा है, जबकि ट्रंप 2.0 के तहत संरक्षणवादी

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र ने जुलाई–सितंबर तिमाही में 3.5 की वृद्धि दर्ज की है। आगे भी अनुकूल मानसून की संभावना है। कृषि वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में तेजी आई है जो शहरी मंदी का प्रतिकार करती है।

व्यापार नीतियों की संभावित वापसी भारत के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। घरेलू मोर्चे पर विनिर्माण वृद्धि पिछली तिमाही में तेजी से गिरते हुए 7 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत तक नीचे आ गई है, जो व्यापक आर्थिक कमजोरी को दिखाती है। खासकर निम्न आय समूह में शहरी खपत भी कमजोर हुई है। लगभग 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और स्थिर मजदूरी ने क्रय शक्ति को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। खाद्य मुद्रा स्थिति का स्तर 10 प्रतिशत से अधिक होने से घरेलू वित्तीय तनाव बढ़े हैं, जिससे कि विवेकाधीन खर्च और खपत के स्तर में भारी कमी दर्ज की गई है। निजी खपत जुलाई–सितंबर तिमाही में सिर्फ 6 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही के 7 प्रतिशत के आंकड़े से कम है। शहरी भारतीयों का खर्च जीडीपी की वृद्धि में अहम योगदान करता है लेकिन यह तबका मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी में स्थिरपन या गिरावट का सामना कर रहा है। अक्टूबर 2024 के बाद से पूंजी बहिर्वाह के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। निवेशकों के विश्वास में कमी आई है। दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा दरों को आपेक्षित रूप से कम करने में अनिच्छा प्रकट करने के कारण विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार अब कम आकर्षक बन गए हैं।

चुनौतियों के बीच उज्जवल स्थान

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र ने जुलाई–सितंबर तिमाही में 3.5 की वृद्धि दर्ज की है। आगे भी अनुकूल मानसून की संभावना है। कृषि वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में तेजी आई है जो शहरी मंदी का प्रतिकार करती है। यदि लक्षित सरकारी उपायों द्वारा इसे पर्याप्त रूप से समर्थन किया जाता है तो यह ग्रामीण मांग अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ज्ञात हो कि सार्वजनिक व्यय अपने स्वस्थ गति से लगातार चल रहा है जो की आर्थिक प्रतिकूलताओं के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। 80 करोड लोगों को मुक्त राशन दिया जा रहा है।

मौद्रिक प्रोत्साहन एक 'दो–धारी तलवार'

अभी देश में सबसे अधिक बहस मौद्रिक प्रोत्साहन को लेकर चल रही है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति संबंधी चिताओं को आगे करते हुए बेंचमार्क ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत से कम करने की मांग का विरोध किया है। फिर कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में दरों में कटौती की जरूरत है। उनका तर्क है कि उच्च आधार लागत क्षमता निर्माण और नए निवेश को हतोत्साहित करते हैं, जिससे विनिर्माण और शहरी मांग में मंदी उपजती है।

हालांकि ब्याज दरों में कटौती कोई रामबाण नहीं है, लेकिन इससे वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बढ़ावा मिलता है। कम उधार लागत ऋण चुकौती के बोझ कम कर सकते हैं, जिससे खपत को बढ़ावा मिल सकता है। कम वित्तीय पोषण लागत से व्यवसाय भी लाभान्वित हो सकते हैं। संभावित रूप से निवेश गतिविधि फिर से पटरी पर आ सकती है। हालांकि मौद्रिक सहजता का प्रभाव आमतौर पर देरी से संचालित होता है जो पूरक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

संरचनात्मक सुधार समय की मांग

केवल मौद्रिक सहजता मंदी के मूल कारणों को संबोधित नहीं कर सकती। विनिर्माण क्षमता की अधिकता से निपटने, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को कमजोर करने वाले सस्ते आयातों की डंपिंग को रोकने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक है। सरकार को तकनीकी प्रगति को भी प्राथमिकता देनी चाहिए और वैश्विक बदलावों का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए 'चीन प्लस वन' रणनीति, जिसका उद्देश्य चीन से परे आपूर्ति श्रंखलाओं में विविधता लाना है। दुर्भाग्य से भारत ने इस अवसर का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया है। आपूर्ति पक्ष के मसले महत्वपूर्ण है, जबकि मंदी का प्रमुख कारण मांग पक्ष है। इस समय खपत, निवेश तथा मांग सभी कमजोर स्थिति में है। बड़ी कंपनियों ने मुनाफे के बाद भी क्षमता विस्तार, वेतन में वृद्धि आदि को बांधकर रखा है। इसके चलते निवेश चक्र में ठहराव है तथा मांग में कमी है।

वर्तमान मंदी से उबरने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। इसके लिए समावेशी और सतत विकास का नजरिया जरूरी है, जो लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देता हो।

आगे का रास्ताः समन्वित नीति कार्रवाई

भारत की अर्थव्यवस्था मौलिक रूप से लचीली है, लेकिन वर्तमान मंदी के चेतावनी संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए संभावित प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले मंदी से प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय नीति का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना मांग को उत्तेजित करने का रास्ता तैयार हो सके।

दूसरा, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यदि मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हो जाता है तो रिजर्व बैंक उधार लेने और निवेश का समर्थन करने के लिए ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है।

तीसरा, दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधारों को तेज किया जा सकता है। श्रम उत्पादकता में सुधार बुनियादी ढांचों को बढ़ाने और नियामक ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से नीतियां निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकती है। और अंत में निर्यात संवर्धन पर मुख्य ध्यान होना चाहिए। व्यापार साझेदारी को मजबूत करना, निर्यात में विविधता लाना, वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्थात्मकता को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। वर्तमान मंदी से उबरने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। इसके लिए समावेशी और सतत विकास का नजरिया जरूरी है, जो लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देता हो।

मोटे तौर पर मंदी चिंताजनक तो है, लेकिन यह विकास के कारकों पर पुनर्विचार करने और उन्हें पुनः संतुलित करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। नवाचार, समन्वित नीतिगत कार्रवाई और संरचनात्मक सुधारों के जरिए भारत अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिकी सदैव लचीली रही है। फिर भी मंदी की चुनौतियां विकट है लेकिन इस आपदा में अवसर भी है। भारत अपनी कमजोरी को दूर करते हुए अंतर्निहित शक्तियों को दोहन कर न केवल मंदी से उबर सकता है बल्कि भविष्य में उच्च विकास का मॉडल भी पेश कर सकता है। ध्यान रहे विकास का अर्थ सिर्फ जीडीपी संख्या हासिल करना नहीं है, यह राष्ट्र की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह समय उठ खड़े होने और उचति कार्रवाई करने का है। सकारात्मक बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2026 में देश की जीडीपी 7 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि मानसून एक बार और सामान्य रहने वाला है। ❑❑

भव्यता से अधिक दिव्यता का पोषक रहा है भारतीय आर्थिक दर्शन

वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में यह कहा गया है कि मानव जीवन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का करना आवश्यक है। अच्छे कर्म अर्थात हमारे किसी कार्य से किसी पशु, पक्षी, जीव, जंतु को कोई दुःख नहीं पहुंचे एवं सर्व समाज की भलाई हो। अर्थात, इस धरा पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, मंगल हो। ऐसी कामना भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में की जाती है।

इसी प्रकार, धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नारद की नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि 'अर्थशास्त्रास्तु बलवत धर्मशास्त्र नीतिस्थिति'। अर्थात, यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नैतिकता के सिद्धांत के बीच कभी विवाद उत्पन्न हो जाए तो दोनों में से किसे चुनना चाहिए। कौटिल्य, नारद एवं याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना में यानी केवल पैसा कमाने के सिद्धांतों की तुलना में हमको धर्मशास्त्र के सिद्धांत अर्थात नैतिकता, संयम, जिससे समाज का भला होता हो, उसको चुनना चाहिए। कुल मिलाकर अर्थतंत्र धर्म के आधार पर चलना चाहिए। नोबेल विजेता गुनार मिर्डल ने अपनी किताब 'अगेन्स्ट द स्ट्रीम' में अर्थशास्त्र को एक नैतिक विज्ञान बताया है। कुछ वर्ष पूर्व अखबारों में एक खबर छपी थी कि विश्व बैंक ने यह जानने के लिए एक अधय्यन प्रारम्भ किया है कि विकास में आध्यात्म की कितनी भूमिका है। इसी प्रकार दुनिया में यह जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि दरिद्रता मिटाने में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है।

प्राचीन भारत के वेद–पुराणों में धन अर्जित करने को बुरा नहीं माना गया है। प्राचीन काल में वेदों के भाष्यकार यास्क ने 'निघंटू' नामक ग्रंथ में धन के 28 समानार्थ शब्द बताए हैं, और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। दुनिया की किसी पुस्तक में अथवा किसी अर्थशास्त्र की किताब में धन के 28 समानार्थ शब्द नहीं मिलते हैं। भारत के शास्त्रों में धन के सम्बंध में उच्च विचार बताए गए हैं। भारत के शास्त्रों ने अर्थ के क्षेत्र को हेय दृष्टि से नहीं देखा है एवं यह भी कभी नहीं कहा है कि धन अर्जन नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए। बल्कि दरिद्रता एवं गरीबी को पाप बताया गया है। हां, वेदों में यह जरूर कहा गया है कि जो भी धन कमाओ वह शुद्ध होना चाहिए। 'कालाध न' नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार करके धन नहीं कमाना चाहिए, स्मग्लिंग करके धन नहीं कमाना चाहिए, कानून का उल्लंघन करते हुए धन अर्जन नहीं करना चाहिए, ग्राहक को धोखा देकर धन नहीं कमाना चाहिए। मनु स्मृति में तो मनु महाराज ने कहा है कि सब प्रकार की शुद्धियों में सर्वाधिक महत्व की शुद्धि अर्थ की शुद्धि है। भारतीय शास्त्रों में खूब धन अर्जन करने के बाद इसके उपयोग के सम्बंध में व्याख्या की गई है। अर्जित किए धन को केवल अपने लिए उपभोग करना, उस धन से केवल ऐय्याशी करना, केवल अपने लिए काम में लेना, अपने परिवार के लिए मौज मस्ती करना, आदि को ठीक नहीं माना गया है। अर्जित किए गए धन को समाज के साथ मिल बांटकर, समाज के हितार्थ उपयोग करना चाहिए।

भारत के प्राचीन ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य को पुरुषार्थ से जोड़ते हुए यह कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों बातों पर विचार करके मनुष्य को सुखी करने के

किसी भी देश का आर्थिक विकास इस तरह से हो कि उस देश के समस्त नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से होती रहे, वे सम्पन्न बनें एवं खुश रहें।

– प्रहलाद सबनानी

सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के चलते भारत के मनीषियों द्वारा अर्थ और काम को नकारा नहीं गया है। कई बार भारत के बारे में वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाता रहा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में तो अर्थ और काम को नकार दिया गया है। प्राचीन काल में भी ऐसा कतई नहीं हुआ है। अगर, ऐसा हुआ होता तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनता? हां, भारत के प्राचीन शास्त्रों में यह जरूर कहा गया है कि अर्थ और काम को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थ और काम को मर्यादा में ही रहना चाहिए।

भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में बोलबाला था। भारत के ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिक बहुत सम्पन्न हुआ करते थे। कृषि उत्पादकता की दृष्टि से भी भारत का पूरे विश्व में डंका बजता था तथा खाद्य सामग्री एवं कपड़े आदि उत्पादों का निर्यात भारत से पूरे विश्व को होता था। भारत के नागरिकों में देश प्रेम की भावना कूट–कूट कर भरी रहती थी तथा उस खंडकाल में भारत का वैभव चरम पर था, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में नागरिक आपस में भाई चारे के साथ रहते थे एवं आपस में सहयोग करते थे। केवल 'मैं' ही तरक्की करूं इस प्रकार की भावना का सर्वथा अभाव था। 'हम' सभी मिलकर आगे बढ़ें, इस भावना के साथ ग्रामीण इलाकों में नागरिक प्रसन्नता के साथ अपने अपने कार्य में व्यस्त एवं मस्त रहते थे।

प्राचीन काल में भारत में भव्यता के स्थान पर दिव्यता को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। भव्यता का प्रयोग सामान्यतः स्वयं के विकास के लिए किया जाता है। जबकि दिव्यता का उपयोग समाज के विकास में आपकी भूमिका को आंकने के पश्चात किया जाता है। भव्यता दिखावा है, भव्यता प्रदर्शन है, अतः केवल भव्यता के कारण किसी का जीवन ऊंचाईयों को नहीं छू सकता है, इसके लिए दिव्यता होनी चाहिए, अर्थात समाज की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करना होता है।

अर्थ को धर्म से जोड़ने के साथ ही, प्रकृति के संरक्षण की बात भी भारतीय पुराणों में मुखर रूप से कही गई है। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार नदियों, पहाड़ों, जंगलों, जीव जंतुओं में भी देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यह कहा गया है कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करें, शोषण नहीं करें। सर जगदीश चंद्र बसु ने एक परीक्षण किया और इस परीक्षण के माध्यम से यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी वैसी ही संवेदना होती है जैसी मनुष्यों में संवेदना होती है। जिस प्रकार मनुष्य रोता है, हंसता है, प्रसन्न होता है, नाराज होता है, इसी प्रकार की संवेदनाएं पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। सर जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक तरीके से जब यह सिद्ध किया तो दुनिया में तहलका मच गया। जबकि भारतीय शास्त्रों में तो इन बातों का वर्णन सदियों पूर्व ही मिलता है। जब इन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार दिया गया तो अब पूरी दुनिया भारत के इन प्राचीन विचारों पर साथ खड़ी नजर आती है।

अर्थ के विभिन्न आयामों को समझने के लिए भारत के प्राचीन काल में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। आचार्य चाणक्य को भारत में अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि नागरिकों को संतुष्टि प्रदान करने (वस्तुओं एवं सेवाओं का भारी मात्रा में उत्पादन कर उसकी आसान उपलब्धता कराना) के उद्देश्य से उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, आदि) का दक्षतापूर्ण वितरण करना ही अर्थशास्त्र है।

दुनिया में कोई भी विचारक जब कभी भी आर्थिक विकास के बारे में सोचता है अथवा इस सम्बंध में कोई योजना बनाने का विचार करता है तो सामान्यतः उसके सामने मुख्य रूप से यह उद्देश्य रहता है कि उस देश का आर्थिक विकास इस तरह से हो कि उस देश के समस्त नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से होती रहे, वे सम्पन्न बनें एवं खुश रहें। इस प्रकार, नागरिकों में प्रसन्नता का भाव विकसित करने में अर्थ के योगदान को भी आंका गया है। कई बार भारतीय समाज में यह उक्ति भी सुनाई देती है कि "भूखे पेट न होहि भजन गोपाला" अर्थात यदि देश के नागरिकों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होगी तो अध्यात्मवाद की ओर वे किस प्रकार मुड़ेंगे। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि धर्म के बिना अर्थ नहीं टिकता, अर्थात धर्म एवं अर्थ का आपस में सम्बंध है। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

भारत की आर्थिकीः दशा और दिशा

भारत की आर्थिक नीतियों की चर्चा हमेशा से होती रही है। यह बात सही है कि एक जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन स्वतंत्रता के पहले कई शतकों तक यह देश लूटता रहा और अंग्रेज़ तो इस देश को कंगाल और 'भीखमंगा' करके ही गए। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय आर्थिक नीतियां घोषित उद्देश्यों के प्रति स्थिर नहीं रही और इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय नेतृत्व और यहाँ के नीतिकारों ने सारी नीतियां बाहर से उधार ली है और उसे भारतीयों पर थोपने का काम किया है। बाहरी नीतियां उपयुक्त नहीं रही ऐसा नहीं है। पाश्चात्य दृष्टि से वे उपयोगी रही है, यही कह सकते है, लेकिन इस देश की समस्याओं का हल वे नहीं ढूंढ पाई, यह हकीकत समझना भी जरूरी है।

भारतीय आर्थिक नीतियों की शुरुवात रशियन मॉडल से

स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्रीय योजना के तहत केंद्रीय मार्गदर्शन और सहायता से अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रभावशाली क्षेत्र का विकास सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा करने की नीति बनाई। इस नीति का आधार रशियन साम्यवादी मॉडल था, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करेगी वह सरकार करेगी यह इस नीति का मुख्य अंग था। इस के तहत संसाधनों को सरकार द्वारा विशिष्ट क्षेत्र की ओर मोड़ा गया। निश्चित ही संसाधनों की कमी थी इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर्ज लेकर ही इस मॉडल ने काम किया। मूलभूत उद्योग से जो सुविधाएं या इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उससे विकास निचले स्तर पर टपकेगा और निजी पूंजी द्वारा निचले उद्योग विकसित होने की बात सही साबित नहीं हुई। सरकारी बाबुओं की मनमानी चली और उसके परिणामस्वरूप भारत आर्थिक विकास की समस्याओं से जुझता रहा और इस दौरान पिछड़े देशों की सूची में ही शामिल रहा।

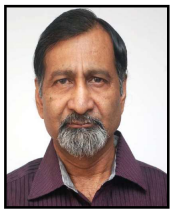

जरूरी है कि भारत अपनी आर्थिक नीतियाँ भारतीय विचार और भारतीय परिपेक्ष्य में निर्धारित करें और राजनीति को आर्थिक नीतियों पर हावी न होने दे।

–अनिल जवलेकर

गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रमों का दौर

आर्थिक नीति का दूसरा मॉडल श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुआ। वे जब प्रधानमंत्री बनी तो पिछड़ापन के साथ–साथ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याएँ देश को घेरे हुई थी। भारत अमरीका के गेहूँ पर ही जी रहा था। पिछड़े लोग और पिछड़ा क्षेत्र पीछे ही छूटता जा रहा था और उसे आर्थिक मदद की जरूरत थी। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को नए तरीके से घोषित किया गया और इस क्षेत्र में आर्थिक मदद बढ़े इसलिए प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 'गरीबी हटाओ' की घोषणा कर आर्थिक पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े लोगों के लिए कर्ज और सब्सिडी की व्यवस्था की गई। कर्ज–मेले लगने लगे जिससे आगे चलकर बैंकों के आर्थिक क्षमता पर असर हुआ। कर्ज डूबने की समस्या आयी और बैंकों को ही मदद की जरूरत पड़ने लगी। गरीबी तो हटी नहीं उससे भारतीय वित्तीय व्यवस्था बिगड़ने लगी। यह मॉडल भी विदेशी विचारों से ही प्रेरित था।

आर्थिक सुधारों का दौर

1990 तक चले इन दो मॉडलों ने देश की कंगाली बढ़ाई और देश आर्थिक दृष्टि से डूबने की कगार पर आ पहुंचा। 'करेगी तो सिर्फ सरकार' की नीति का अपयश इसका मुख्य कारण था और उसे बदलना मजबूरी हो गई। इसी समय दुनिया के विकसित देश

जागतिकरण और खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारने पर ज़ोर डाल रहे थे और भारत को भी इसको स्वीकारना पड़ा। यह नरसिंहराव–मनमोहन सिंह का दौर था। सब कुछ सरकार करेगी, को भूलकर सब कुछ निजी क्षेत्र पर छोड़ने की नीतियाँ बनने लगी। परिणामस्वरूप निजी उद्योग सांस लेने लगे और बाबूगिरी कम हुई। आर्थिक विकास दर बढ़ा और भारत विकास की ओर मुड़ा।

स्वयंसेवी संस्था द्वारा विकास का प्रयास

ऊपरी तीनों मॉडल से गरीबी और बेरोजगारी समस्या हट नहीं रही थी और सरकार ग्रामीण पिछड़ापन को समाप्त करने में नाकामयाब हो रही थी। इसलिए एक तीसरा मॉडल आजमाया गया जिसके द्वारा विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी सेवा संघटनों की सहायता ली जानी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा अन्य एनजीओ के प्रभाव का यह दौर था। इनके द्वारा कर्ज और अनुदान पर आधारित व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के ग़रीब उसमें भी महिला का सहयोग इसमें उपयुक्त रहा। यह मॉडल कुछ हद तक सफल रहा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सक्षम बनाने में कामयाब रहा। फिर भी पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या कम नहीं हुई।

विदेशी पूंजी, विदेशी व्यापार और तंत्रज्ञान

जागतिकरण तथा खुली अर्थव्यवस्था ने विकास की नैया आज निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दी है। इस नीति में विदेश पूंजी, विदेशी व्यापार और तंत्र ज्ञान विकास और उसका उपयोग महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आज दुनिया इसी मॉडल के तहत आर्थिक नीतियाँ बना रही है। भारत ने भी इसे अपनाया है। यह सही है कि भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है और इसे प्रोत्साहित करने हेतु कुछ

भारत गत 75 वर्षों में अपनी 'भीख मंगा' देश होने की पहचान मिटा चुका है और अपने को एक समर्थ और प्रभावशाली देश प्रस्थापित करने में कामयाब हुआ है।

कार्यक्रम अमल में लाये जा रहे है। लेकिन विदेशी पूंजी भारत में आए और भारत का विदेशी व्यापार बढ़े इसके लिए भी नीतियाँ अपनाई जा रही है। यहाँ तक कि रुपए को भी अंतरराष्ट्रीय चलन के रूप में पेश करने की कोशिशें हो रही है। भारत ने नया तंत्र ज्ञान अपनाया है और भारत शासकीय तथा आर्थिक व्यवस्था डिजिटल करने में सबसे आगे है।

भारत की आर्थिक नीतियों कि दिशा

भारत स्वतंत्र हुए 75 वर्ष बीत चुके है और आज भारत अपनी आर्थिक नीतियों से 'विकसित भारत' का सपना देख रहा है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत गत 75 वर्षों में अपनी 'भीख मंगा' देश होने की पहचान मिटा चुका है और अपने को एक समर्थ और प्रभावशाली देश प्रस्थापित करने में कामयाब हुआ है तथा अब विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रगति में सबसे ज्यादा भूमिका भारत के कृषि क्षेत्र ने निभाई है क्योंकि इसी क्षेत्र ने भारत को अन्न में आत्मनिर्भर बनाया है। आज कृषि क्षेत्र विदेशी व्यापार में भारत को विदेशी चलन के प्राप्ति में भी मदद कर रहा है। भारत के शिक्षित युवाओं ने तो दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और तंत्र ज्ञान में कुशलता हासिल की है। सेवा क्षेत्र भारत का मुख्य क्षेत्र इसी कारण बना हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक सुधार की नीति कामयाब रही है और भारत के निजी क्षेत्र ने अपेक्षित भूमिका निभाई है। एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी आर्थिक विकास को ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है।

भारत की आर्थिक दशा

भारतीय आर्थिक नीतियों ने भारत को पाश्चात्य विचार दृष्टि से प्रगतिशील देश बनाया है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद भारत की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं रही। अभी भी भारत एक अन्न–धान्य के सिवाय बहुत से क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और अपनी कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है। भारत के शिक्षित बेरोजगारों की समस्या इसमें मुख्य मानी जा सकती है जो की पाश्चात्य शिक्षण विचार स्वीकारने का परिणाम है। अर्थ व्यवस्था में 'उत्पादन क्षेत्र'का कम होता हिस्सा भी इसका कारण बताया जाता है जो पाश्चात्य आर्थिक व्यापार विचारों का परिणाम कहा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भी समस्याओं की कमी नहीं है। यह भुला नहीं जा सकता की पर्यावरणीय बदलाव कभी भी कृषि उत्पादन कम कर सकते है। किसान भी उनको मिलने वाली उत्पादनआय से खुश नहीं है और आए दिन आंदोलित रहते है। इसका भी कारण भारत की कृषि नीतियाँ पाश्चात्य विचार और विदेशी तंत्रज्ञान पर आधारित है यह है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय राजनीति बाहरी ताकतों से मिलकर आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने में लगी हुई दिखती है और यही भारत की आर्थिक दशा को खराब कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत अपनी आर्थिक नीतियाँ भारतीय विचार और भारतीय परिपेक्ष्य में निर्धारित करें और राजनीति को आर्थिक नीतियों पर हावी न होने दे। ❑❑

औद्योगिक क्षेत्र से श्रमिकों का कृषि की ओर बढ़ता रुझान

शहरों में जाकर काम करने वाले भारत के लोग बड़ी संख्या में अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के श्रमिकों को 'कम मुनाफादायक' कृषि से शहरी केंद्रों में बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में धकेलने वाली नीति–समर्थित चाल पिछले पांच सालों में उलट गई लगती है। रिवर्स माइग्रेशन (गांवों की और वापसी) में तेज़ी का संकेत सबसे पहले कोविड–19 महामारी के दौरान मिला, जब लाखों शहरी ग़रीबों ने लंबी दूरी तय की, ज़्यादातर पैदल– जिसे विभाजन के दिनों के बाद लोगों के सबसे बड़े आवागमन के रूप में देखा गया। इस अभूतपूर्व अंतर–राज्यीय या फिर राज्य के भीतर ही हुए स्थानांतरण को पहले अस्थायी माना गया था, लेकिन इस उम्मीद को धता बताते हुए कि महामारी खत्म होने के बाद कार्यबल शहरों में वापस लौट आएगा, अधिकांश प्रवासियों ने अपने मूल स्थान पर ही रहना चुना।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और नई दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान ने एक रिपोर्ट में पहली बार कृषि संबंधी रोज़गार में लगे लोगों की संख्या में वृद्धि पर मुहर लगाई है। आम धारणा के विपरीत, अनुमान है कि 2020 और 2022 के बीच ग्रामीण कार्यबल में 5.6 करोड़ श्रमिक जुड़े। इससे पता चलता है कि बेरोजगारी के साथ विकास के आलम में, शहरों में उपलब्ध रोजगार अवसर प्रवासियों के लिए अब आकर्षक नहीं रहे। चाहे यह मेन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में बनी मंदी की वजह से हो या निर्माण क्षेत्र की नौकरियों में गिरावट की वजह से, प्रवासियों ने गांव वापसी करना बेहतर समझा।

अलबत्ता, इसके बाद सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023–24 ने आर्थिक डिजाइन के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन में उलटफेर दिखाया – जो कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खेती से दूर चले जाने को लेकर था। रोचक है कि 2004–05 और 2018–19

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओएलसीडी) के अनुसार, 54 प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई बजटीय प्रावधानों के जरिये नहीं की जाती।

– देवेन्द्र शर्मा

के 13 साल में 6.6 करोड़ कृषि कार्यबल ने शहरों में छोटे–मोटे रोजगार की तलाश में पलायन किया था लेकिन जेएनयू के अर्थशास्त्री हिमांशु के मुताबिक, अगले पांच सालों (2018–19 से 2023–24) के बीच 6.8 करोड़ लोगों की गांव वापसी हुई। ऐसा नहीं है कि कृषि अचानक से लाभदायक हो गई, लेकिन जिस प्रकार रिवर्स माइग्रेशन की दर ने आर्थिक नीति के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन करवाने के अपेक्षित फायदों को उलट दिया है, उसने दिखा दिया है कि लोगों को खेती छुड़वाने वाली रणनीति व्यवहार्य नहीं थी।

पीएलएफएस सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण कार्यबल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2018–19 में 42. 5 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 46. 1 प्रतिशत हुआ है, जोकि खेती में फिर से जुड़ा कुल आंकड़ा है– और इसमें युवाओं की बड़ी संख्या है – इससे जो संदेश मिलता है उसे अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि लोकप्रिय आर्थिक सोच एक दोषपूर्ण प्रारूप पर आधारित है, जिसने लोगों को इस क्षेत्र से बाहर करने की चाह से सालों तक कृषि को जानबूझकर घाटे का व्यवसाय बनाए रखा ताकि मजबूर होकर शहरों की और पलायन हो। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले आंदोलन के बाद कृषकों के प्रदर्शनों में बड़ी संख्या, उचित आय से महरूम रखने के विरुद्ध उनका रोष दर्शाती है।

यह साल 1996 था जब विश्व बैंक ने चाहा था कि भारत के 40 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र से बाहर निकाला जाना चाहिए – जोकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी के दोगुने के बराबर है – ताकि उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़े और वहां श्रमबल उपलब्ध हो। जबकि पलायन में सहायक बनने वाली स्थितियां बनाने के बजाय खेती को व्यवहार्य उद्यम बनाकर कृषि के पुनर्निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए था। यही महात्मा गांधी चाहते थे, और जिस दर से प्रवासी वापस लौटे हैं, उससे पता चलता है कि वे कितने सही थे। इसलिए, अब समय है कि विश्व बैंक की उक्त नीति को खारिज कर कृषि को पुनर्जीवित करने और खेती को एक टिकाऊ, व्यवहार्य और लाभकारी उद्यम बनाने पर फोकस किया जाए।

अगर आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021–22 की रिपोर्ट देखें। इसके अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कृषि में लगी आबादी का हिस्सा काफी बढ़ गया है। साल 2016–17 में 48 प्रतिशत से 2023–24 में 57 फीसदी के उच्च स्तर तक, कृषि परिवारों की संख्या में भारी उछाल स्पष्ट रूप से मूल निवास पर वापसी की ओर इशारा करता है। पंजाब को छोड़कर, जहां कृषि में लगे परिवारों की हिस्सेदारी 2016–17 में 42 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 36 प्रतिशत रह गयी, हिमाचल में 70 से 63 प्रतिशत व गुजरात और कर्नाटक में थोड़ी–बहुत वृद्धि है। कुल मिलाकर,कई राज्यों में कृषि में लगे परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गोवा में कृषि परिवारों की संख्या 3 फीसदी से बढ़कर 18 प्रतिशत, हरियाणा में 34 से 58 प्रतिशत, उत्तराखंड में 41 से 57 प्रतिशत और तमिलनाडु में 13 से 57 प्रतिशत हो गई है। अधिकांश अन्य राज्य भी कृषि की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं।

कारण जो भी हों, आईएलओ, पीएलएफएस और नाबार्ड के ये तीन सर्वेक्षण और अध्ययन रोजगार और आजीविका चुनौतियों का सामना करने में कृषि का महत्व दिखाते हैं, घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस क्षेत्र की क्षमता को न भूलें। जबकि मुख्यधारा की आर्थिक सोच रिवर्स माइग्रेशन की उस दर से निराश है जिसने कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या कम करने के सभी पिछले पैंतरों को उलट दिया, मुख्यधारा के अर्थशास्त्री और आर्थिक लेखक कृषि रोजगार में वृद्धि को 'चिंताजनक' और 'चिंता का विषय' के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में देखा जा रहा विपरीत पलायन का यह नमूना निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए अनूठा है, लेकिन यह कृषि के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नीतियों को पुनर्जीवित करने की बढ़ती आवश्यकता का संकेत है।

बदलती जमीनी हकीकत को स्वीकार करने का समय आ गया है। कृषि पर निर्भरता अपने आप ही व्यवहार्य रास्ते बना लेगी, बशर्ते सरकार पर्याप्त संसाधन लगाने को तैयार हो। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अर्थशास्त्रियों को कृषि के लिए बजटीय परिव्यय में किसी भी प्रस्तावित वृद्धि को राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओएलसीडी) के अनुसार, 54 प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई बजटीय प्रावधानों के जरिये नहीं की जाती। जैसा कि यह लेखक अक्सर कहता आया है, किसान लगभग 25 वर्षों से साल–दर–साल 'घाटे की फसल' काट रहे हैं। किसानों को 'भगवान भरोसे' छोड़ने वाला यह दोषपूर्ण आर्थिक डिजाइन समाप्त होना चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन को शुभ समाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि संसाधनों को वहां लगाया जाए, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरकार इसी से बनेगा : सबका साथ, सबका विकास। ❑❑

(लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

मिट्टी के ऊपर भुरभुरा और स्नेहिल तत्त्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती पर जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में आठ अरब लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित के करने, बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में घिरा है। मिट्टी का बड़े पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे–धीरे बढ़ रही है, प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों के कारण दबे पांव फैल रहा है।

मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीले रसायनों के संदूषण और फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे आते हैं। मृदा क्षरण आमतौर पर मौजूदा रसायनों (जिसमें खाद और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं) के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगल की कटाई, बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और जलवायु परिवर्तन से । तापमान आदि कारणों से पैदा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती–किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, दस लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। मिट्टी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुताबिक भारत में लगभग एक तिहाई मिट्टी के यानी लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण के दायरे में है, जिसका अच्छा–खासा हिस्सा समुद्र के लवणीकरण से प्रभावित है।

बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद, तकनीक आधारित गहन कृषि के कारण पैदावार में वृद्धि हुई और अब भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वह खाद्य

भारत में प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

– विजय गर्ग

उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मगर बाढ़ के दौरान और निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, रासायनिक खाद के व्यापक इस्तेमाल से जमा होती लवणता, बढ़ती अम्लीयता और जलभराव आदि से कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर होता जा रहा है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद्य आयात करना पड़ सकता है, जबकि भारत, दुनिया के केवल 2.4 फीसद भूमि क्षेत्र के साथ, विश्व की 18 फीसद आबादी को खिलाने में सक्षम है।

मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ–साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और यह वर्षा और हवा के कारण कटाव का शिकार हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है और डेढ़ अरब लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है। साथ ही उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखरखाव और अक्षम प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है। इन सबका असर अंततः मिट्टी पर पड़ता है।

आजादी के बाद अनाज की बढ़ती जरूरत और खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ, जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्त्व कम होने लगे। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए। वर्तमान में कृषि कार्य में 94 फीसद तक रसायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। यहां तक कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया। हरित क्रांति के दौरान हमारा अनाज उत्पादन पांच करोड़ टन से बढ़ कर तीस करोड़ टन पहुंच गया, पर यह उपलब्धि उपजाऊ मिट्टी की कीमत पर हासिल की गई प्रतीत होती है। ऐसे में मिट्टी का तेज गति से क्षरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा के गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मृदा क्षरण के कारण न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन की मात्रा कम हो जाने से इसकी पानी सोखने और जकड़ कर रखने की क्षमता भी काफी हद तक घट जाती है। नतीजा यह कि पानी के स्रोतों से जल का पुनर्भरण काफी कम हो जाता है, जो भारत में बड़े स्तर के भूजल स्तर में गिरावट और सूखे की बढ़ रही समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, जो भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादक हैं, वहां जल स्तर खरतनाक रूप से गिर चुका है। समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।

उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने

समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।

किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्त्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो है। जरूरत । है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती–किसानी को प्रोत्साहन मिले। हालांकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका शामिल है।

भारत में प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी पानी का संकट हमारे खेतों से होते हुए हमारी थाली तक आ पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। ❑❑

तेजी से पनप रही है डिब्बा बंद भोजन संस्कृति!

पहले की तुलना में आज हमारी जीवनशैली बहुत बदल गई है। सच तो यह है कि आज हम आपा–धापी और दौड़–धूप भरी जिंदगी जी रहे हैं। समय होते हुए भी आज हमारे पास दूसरों के लिए तो दूर की बात, स्वयं के लिए भी समय नहीं बचा है। समय के अभाव में हम अपने रहन–सहन, खान–पान पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खान–पान पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इससे हमारी जीवनशैली पूरी तरह से बदल गई है। आज हम सभी पाश्चात्य सभ्यता –संस्कृति (वेस्टर्न कल्चर) के प्रभाव के बीच जी रहे हैं और हमारी इस बदलती जीवनशैली का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

आज हम अपने जीवन में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास न तो भोजन बनाने का समय ही बचा है और न ही इसे ठीक से खाने का। हम इत्मिनान से भोजन करते नहीं,उसे निगलते हैं। विशेषकर आज महानगरों में डिब्बा बंद भोजन की संस्कृति पनपती चली जा रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि ताजा भोजन, ताज़ा ही होता है और डिब्बा बंद भोजन की तुलना में कहीं अधिक पौष्टिक और पोषण युक्त। डिब्बा बंद भोजन कभी भी ताज़ा भोजन का मुकाबला नहीं कर सकता है, भले ही कोई कुछ भी कहे। यह ठीक है कि थर्मल प्रोसेसिंग (खाद्य पदार्थ) से विभिन्न खाद्य उत्पाद डिब्बों में पूरे साल उपलब्ध रहते हैं और इनकी उपलब्धता भी कहीं अधिक आसान और सरल है। यह भी ठीक है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को प्रसंस्करण, जीवाणुरहित (गर्म या ठंडा करके) किया जाता है और इन्हें कंटेनरों में पैक करके वायुरोधी ढंग से सील किया जाता है, लेकिन चिकित्सकों का यह मानना है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाने से व्यक्ति की जैविक उम्र में इज़ाफ़ा होता है अर्थात बुढ़ापा जल्दी दस्तक देने लगता है।

हालांकि, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ ताजे और जमे हुए खाद्य पदार्थों की तरह ही पौष्टिक हो सकते हैं क्योंकि डिब्बाबंदी से कई पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। उनका यह मानना है कि डिब्बाबंदी की प्रक्रिया से खनिजों, वसा में घुलनशील

अधिक मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड व प्रसंस्कृत भोजन (डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ) का सेवन मनुष्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, यह संस्कृति लाइफस्टाइल डिज़ीज़ को जन्म दे रही है। अतः आज जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को डिब्बाबंद भोजन से परहेज करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएं और अपनी संस्कृति को अपनाएं।

– सुनील कुमार महला

विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहती है, लेकिन डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उच्च ताप के कारण कुछ जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और बी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहां ताजा खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध नहीं होते, विशेषकर सैन्यकर्मियों के लिए। यहां तक कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद करते हैं। यह भी एक तथ्य है कि जिन डिब्बों में इनको (डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ) संरक्षित किया जाता है वे डिब्बे काफी हल्के, टिकाऊ होते हैं, तथा इन्हें भण्डारित करना, इधर–उधर ले जाना और निपटाना आसान होता है और इन सभी गुणों के कारण, ये डिब्बे भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क से तथा अत्यधिक प्रकाश के संपर्क से बचा सकते हैं।

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के नुकसान यह हैं कि डिब्बाबंदी की प्रक्रिया में अक्सर घुले हुए नमक का प्रयोग किया जाता है, और उच्च नमक सामग्री से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नमक के अलावा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी की मात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा,डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ अम्लीय नहीं होते, क्योंकि उन्हें पर्याप्त तापीय उपचार नहीं मिलता, जिससे उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि निर्माता अक्सर डिब्बाबंद सूप में संरक्षण और स्वाद बढ़ाने के लिए सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊतक क्षति, हृदय रोग का खतरा, गुर्दे की दुर्बलता, और हड्डियों का नुकसान आदि समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में, डिब्बाबंद भोजन को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उसमें प्रचुर मात्रा में संरक्षक पदार्थ(प्रतिरक्षक), स्टार्च आदि मिला दिए जाते हैं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में बिस्फेनॉल–ए (बीपीए) जैसे रसायन मिले हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं कभी–कभी, डिब्बों में मौजूद धातु भोजन के अंदर पहुंच जाती है, जिससे भोजन में धातु जैसा स्वाद (धात्विक स्वाद) आ जाता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में वसा व कार्बोहाइड्रेट भी खाने को देर तक चलने लायक बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाते हैं।

चिकित्सकों का कहना है कि रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षित डिब्बाबंद खाना हमारे शरीर में सूजन भी पैदा कर सकता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से व्यक्ति मोटापा, हृदय रोग, दूसरी श्रेणी के मधुमेह व गठिया जैसे रोगों का भी शिकार हो सकता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट अधिक होता है जो मोटापे और हृदय रोगों को जन्म देते हैं।

वास्तव में आज भारतीय परिवारों में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी है तो उसका कारण यह है कि आज लोगों की आय में पहले की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई है और हम भारतीय भी आज पश्चिमी देशों की खान–पान संस्कृति का अनुशरण करने लगें हैं। हमारे बुजुर्ग घर में बने ताजा भोजन, मोटे अनाज को खाने की सलाह देते आए हैं लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के जाल में फंसकर हम डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को अपना रहे हैं। भले ही आज हम अपने बुजुर्गों की खान–पान के प्रति सोच को पुरातनपंथी कहकर नकार रहें हों, लेकिन सच तो यह है कि ताजा भोजन/खाद्य पदार्थों का कोई विकल्प नहीं है।

कहना ग़लत नहीं होगा कि अधिक मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड व प्रसंस्कृत भोजन (डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ) का सेवन मनुष्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, यह संस्कृति लाइफस्टाइल डिज़ीज़ को जन्म दे रही है। अतः आज जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को डिब्बाबंद भोजन से परहेज करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएं और अपनी संस्कृति को अपनाएं। ❑❑

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वजामं ने प्रजनन दर में हो रही गिरावट पर चिंता जताई

स्वदेशी जागरण मंच (स्वजामं) ने कुल प्रजनन दर में 'तेजी से हो रही गिरावट' पर चिंता जताई और सरकार सहित सभी लोगों से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आह्वान किया। मंच का मानना है कहा कि कुल प्रजनन दर में गिरावट होने से जनसंख्या में 'खतरनाक असंतुलन' हो सकता है और इससे देश का विकास भी धीमा पड़ सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने भी हाल ही में यह मुद्दा उठाया और कहा कि प्रजनन दर (टीएफआर) में हो रही गिरावट को 'गंभीरता' से लिया जाना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच के सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एक बयान में कहा, ''स्वदेशी जागरण मंच कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में तेजी से हो रही गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मंच इसका भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और हमारे समाज के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त करता है।''

मालूम हो कि टीएफआर का तात्पर्य महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने जून में लखनऊ में आयोजित अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई गई थी।

महाजन ने कहा, ''हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखने की समस्या है, ताकि हमारे विकास प्रयासों में कोई बाधा न आए। हमें यह समझना होगा कि यदि हमनें इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया तो इससे निर्भरता का बोझ बढ़ेगा और जनसंख्या में खतरनाक असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे देश के विकास की गति भी धीमी पड़ सकती है।''

महाजन ने बताया कि आरएसएस प्रमुख ने भी टीएफआर के 2.0 से नीचे जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ''लैंसेट के नवीनतम प्रकाशन में बताया गया था कि भारत की कुल प्रजनन दर 2021 तक घटकर 1.91 रह गई है। साथ ही इसने यह भी अनुमान जताया था कि 2050 तक टीएफआर गिर कर 1.29 हो जाएगी। ''

महाजन ने कहा, ''हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि सरसंघचालक जी ने कहा था कि यदि किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है, तो यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए, किसी भी स्थिति में टीएफआर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी आदि में टीएफआर 2.1 से बहुत नीचे पहुंच गई, जिससे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया।'' महाजन ने कहा, ''भारत को इन देशों से सीखना चाहिए और कुल प्रजनन दर में हो रही गिरावट को रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए।''

इस बीच स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान सह प्रांत प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि 1960 में भारत की फर्टिलिटी रेट 6.0 थी, जो 1990 में घटकर 3.4 और अब 2. 1 से नीचे पहुंच गई है। यह गिरावट विकसित देशों की स्थिति की ओर इशारा करती है, जहां कम फर्टिलिटी दर ने सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा किए हैं। युवाओं की घटती संख्या से भविष्य में श्रम शक्ति कमजोर होगी, जिससे देश की आर्थिक उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या के कारण युवाओं पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ेगी।

इस क्रम में स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र संयोजक प्रो. दीपक शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दैरान देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में लगातार आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि जनसंख्या हमारा बाधक नहीं बल्कि साधक है। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है लेकिन जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ियां अपने करियर निर्माण अथवा अन्य कारणों से परिवार बसाने को लेकर विलंब कर रही हैं वह चिंता का विषय है।

https://hindi.theprint.in/india/swadeshi-jagran-manch-expressed-concern-over-the-decline-in-fertility-rate/760386/

बेरोजगारी मिटाने के लिए युवा स्वदेशी की ओर बढ़ें: कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच व स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से गोपाल विद्या मंदिर में प्रांत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वदेशी मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए युवा

स्वदेशी की ओर बढ़ें और अपना उत्पाद तैयार करें। इस प्रांत सम्मेलन और स्वदेशी मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार की ओर ले जाना है। युवा नौकरियों के पीछे नहीं भागें। स्वरोजगार अपना कर नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने।

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार तीन प्रकार के शरीर में दोष पाए जाते हैं। जिसमें, वात, पित्त और कफ शामिल हैं। प्राचीन काल में वैद्य मरीज की प्रकृति के अनुसार ही लोगों की बीमारियों का पता लगते थे और उनका इलाज करते थे। वहीं सह संगठक सतीश कुमार ने स्वदेशी उत्पाद तैयार करके व्यापार करने का संदेश दिया।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढा ने कहा कि भारत सरकार युवाओं को रोजगार देने का अथक प्रयास कर रही है। युवा स्वदेशी अपनाएं और भारत को विकसित बनाएं। वहीं उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉ. सोमनाथ सचदेवा ने अच्छी शिक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता का अध्ययन करने का संदेश दिया।

स्वदेशी जागरण मंच ने की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील

महराजगंज नगर में स्वदेशी जागरण मंच की बैठक हुई। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा युवाओं के रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करते हुए स्वदेश में बने वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ताकि देश स्वावलंबी बन सके।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच उद्यम के क्षेत्र में बेहतर रूप से कार्य कर रहा है। बैठक में संजय राय को जिला संयोजक, अजय पांडेय को सह संयोजक, बृजेश शर्मा को जिला प्रमुख, मनोज गौतम को जिला प्रचार प्रमुख, विनोद कुमार को विभाग प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर संजय मणि त्रिपाठी, साधुशरण, मयंक मणि त्रिपाठी, बुधेश, दीपक मद्धेशिया, मिथिलेश अग्रहरी, राघवेंद्र तिवारी, विशाल त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/maharajganj/story-swadeshi-jagran-manch-meeting-focuses-on-employment-generation-and-boycott-of-foreign-goods-201734493342196.html

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत 2 साल में 8 लाख कारोबारी होंगे तैयारः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक सतीश कुमार ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 30 अन्य सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक संगठनों के सहयोग से मिलकर चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आने वाले 2 साल में 8 लाख युवाओं को रोजगार देने वाला इंटरप्रिन्योर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और संगठन इसे 2 साल में अवश्य ही हासिल कर लेगा।

पंजाब केसरी के साथ विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए इस अभियान की शुरूआत की गई थी और यह अभियान अब लगातार बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के 600 जिलों में चलाया जा रहा है और इसके साथ कालेज, यूनिवर्सिटियां, आई.आई.टी. और पॉलीटैक्निकल कालेजों को जोड़ा गया है और इसके जरिए देश में उद्यमिता को बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की पृष्ठभूमि मोटे तौर पर कारोबारी रही है और अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में नौकरियों का चलन बढ़ा था।

उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और कोरोना के बाद यह समस्या ज्यादा बढ़ गई थी, लिहाजा इस मुद्दे के समाधान के लिए शुरूआत में 8 संगठनों को साथ लेकर रिसर्च अभियान शुरू किया गया, और इस कार्य में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विद्यार्थी परिषद और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों का सहयोग लेकर देश की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी पर रिसर्च की गई। रिसर्च के बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए और इस अभियान की शुरूआत हुई ।

आज भी देश के कुल रोजगार में चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही रोजगार है। जबकि प्राइवेट सैक्टर और कार्पोरेट जगत कुल मिलाकर लगभग सवा 6 प्रतिशत रोजगार का सृजन करता है। देश के 75 से लेकर 80 प्रतिशत तक लोग अभी भी कृषि, स्वरोजगार और छोटी दुकानदारी के अलावा उद्यमिता करते हैं। लेकिन देश में एक अलग तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नौकरी ही रोजगार है। इसी नैरेटिव की धार कम करने और लोगों को अपना रोजगार शुरू करने हेतु प्रेरित करने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान के तहत सफल कारोबारियों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान में ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं, जिन्होंने 1200 रुपए से अपना काम शुरू करके 800 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी की है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य पूर्ण रोजगारयुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत और समृद्धि युक्त भारत है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के शुरू होने के बाद हैदराबाद में लगाए गए एक ही मेले में 4000 लोगों ने रोजगार सृजन के लिए संकल्प लिया और इसके बाद बालाघाट के मेले में भी 3000 लोग स्वरोजगार के साथ जुड़ने का संकल्प लेकर गए।

अब तक देश में 4000 यूनिवर्सिटीज में 8 लाख लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के जरिए अपना रोजगार शुरू करने का संकल्प ले चुके हैं और इनमें से आने वाले दो साल में 8 लाख नए कारोबारी जरूर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले पर सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए और गैर सरकारी संगठनों को इससे जुड़कर अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहिए। क्योंकि जो अभियान अ–सरकारी होता है, वह ही असरकारी होता है।

स्वदेशी महाकुंभ

स्वदेशी जागरण मंच हर साल कुंभ के संगम क्षेत्र में स्वदेशी शिविर का आयोजन करता रहा है। पहला शिविर राष्ट्रऋषि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा उदघाटित किया गया था। इसके बाद 2017 से यह हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष स्वदेशी जागरण मंच ने बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। देश के विभिन्न हिस्सों से स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकताओं को आमंत्रित करने और उनके साथ समन्वय करने और शिविर का प्रबंधन करने के लिए एक कोर टीम का गठन किया गया है । आशा है कि महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्री होली संगम गंगा में डुबकी लगाएंगे। स्वदेशी शिविर 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसमें 50 विभिन्न प्रकार के टेंटों में एक बार में 250 लोग रह सकते हैं।

इस स्वदेशी महाकुंभ का अपना पवित्र उद्देश्य है, लेकिन साथ ही शिविर में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 6 दिसंबर 24 को लगभग 250 स्वदेशी कार्यकताओं की उपस्थिति में शिविर का भूमि पूजन किया गया। स्वदेशी महाकुंभ अपने विभिन्न कार्यक्रमों के बीच स्वावलंबी भारत अभियान के उद्देश्यों को बढ़ावा देगा। स्वदेशी शिविर का कार्यक्रम भी इस नोट के साथ संलग्न है। महाकुंभ में स्वदेशी शिविर ग्रामीण आबादी से सीधा संवाद और संवाद करेगा, जिसमें उदयमिता की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस शिविर के आयोजन में लगभग 1000 स्वदेशी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रयाग राज के कार्यकर्ता काफी सक्रिय और उत्साह से शामिल हैं। अंत में स्वदेशी यात्रा निकाली जाएगी, जो स्वावलंबी भारत अभियान का संदेश देते हुए पूरे महाकुंभ क्षेत्र से गुजरेगी। महाकुंभ में देश और दुनिया भर से आए तीर्थयात्रियों के बीच करोड़ों स्वदेशी विदेशी सूची के पर्चे वितरित किए जाएंगे।

राज्यों में परिवार नियोजन के अभियान बंद हों : सतीश कुमार

सतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा देश में कम हो रही आबादी को लेकर जताई गई चिंता को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश

का टोटल फर्टीलिटी रेट 2.1 प्रतिशत से नीचे जा रहा है और यह निश्चित तौर पर देश के लिए चिंता की बात है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्य बढ़ाने को लेकर इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि देश की आबादी में कमी आ रही है, लेकिन नए आंकड़ों मुताबिक सामने आ रहा है कि पंजाब में टोटल फर्टीलिटी रेट कम होकर 1.6 प्रतिशत रह गया है, जबकि महाराष्ट्र में यह गिरकर 1.5 प्रतिशत रह गया है। यह निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है, क्योंकि आबादी बढ़ने की यह दर 2.1 प्रतिशत से ज्यादा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार द्वारा ही देश में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन का अभियान चलाया गया था और इसमें सफलता भी मिली, लेकिन अब यह अभियान चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में सरकारें यह अभियान चला रही हैं, जिसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 या 3 बच्चे घर और देश को रखते अच्छे। लिहाजा अब देश के युवाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए जनसंख्या का बढ़ना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अब यह चिंता का विषय बनती जा रही है। साऊथ कोरिया में आबादी में वृद्धि की दर 0.7 प्रतिशत रह गई है, जबकि जापान में 1.2 और चीन में 1 प्रतिशत रह गई है। इन देशों में आबादी बढ़ाने के तमाम प्रयास अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। दुनिया के 131 देशों में टोटल फर्टीलिटी रेट 2.1 प्रतिशत से नीचे चला गया है, जबकि 53 देशों में यह रेट 1.5 प्रतिशत रह गया है, जो निश्चित तौर पर चिंता की बात है।

इससे दुनिया भर की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ेगा और साऊथ कोरिया जैसे देश का आने वाले सालों में अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों, साधु संतों, सामाजिक संगठनों और मीडिया को इस बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा सही तथ्य सामने रखे जाएं ताकि समाज से जुड़े लोग इस मामले में सही और समझदारी भरा फैसला ले सकें।

स्वावलंबन केंद्र का शुभारंभ

गत दिनों मल्कागंज (नई दिल्ली) में स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबन केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने स्वदेशी उत्पादों और चीजों पर बल देते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में भारत में ही बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो उसे हम विदेशों में भी भेज सकते हैं। इससे भारत की विदेशी मुद्रा अत्यधिक मजबूत होगी। भाजपा नेता गुरुजी राजू चंदेल ने कहा कि हमें विदेशी चीजों पर निर्भर नहीं रहना है।

गत दिसंबर को भोपाल में 'राष्ट्र सेविका मां अहिल्या बाई होल्कर' पुस्तक का लोकार्पण हुआ। पुस्तक के लेखक हैं विद्या भारत एवं मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री श्री निखिलेश महेश्वरी। कार्यक्रम में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री श्रीराम अरावकर ने कहा कि अहिल्याबाई के विचारों को पढ़ने, उन्हें आत्मसात करने के साथ ही लोकमाता के विषय में और अधिक शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं को अनाम रख लोकहित के कार्य करने में देवी अहिल्याबाई बड़ी उदाहरण एवं प्रेरणा हैं। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक श्री अशोक पांडेय ने की। सारस्वत अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह एवं राज्य सूचना आयुक्त डॉ. वंदना गांधी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

https://panchjanya.com/2024/12/28/378934/bharat/madhya-pradesh/launch-of-swavalamban-center/

स्वदेशी को आगे बढ़ाने से देश होगा समृद्ध : उपाध्याय

स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठक अजय उपाध्याय ने कहा है कि आज देश में स्वदेशी जागरण मंच की

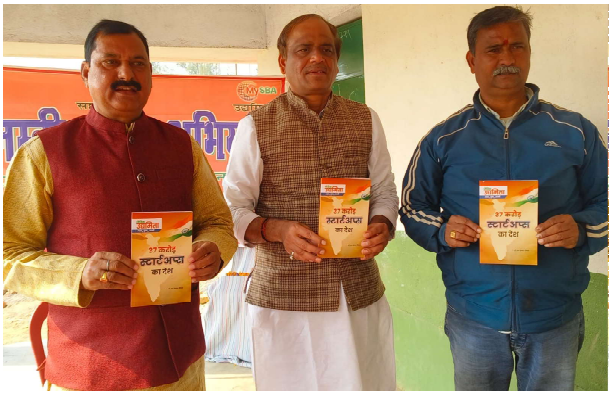

आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता ही स्वदेशी के भाव को जन–जन तक पहुंचा सकते हैं। समाज के बीच हमें संवाद निरंतर बनाए रखना है और स्वदेशी प्रेम और स्वदेशी भाव को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है। स्वदेशी को आगे बढ़ाने से देश समृद्ध होगा। इसके लिए कई अहम विषय हैं जैसे खेती को प्रकृति युक्त बनाना होगा। पशुधन को स्वदेशी रूप में आगे बढ़ना होगा। वे स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

प्रांत सह संयोजक श्यामल दास की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक का शुभारंभ स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उन्होंने कहा कि जो बागवानी हम सब करते हैं उसे औषधि युक्त बागवानी बनाना है। बाजार को स्वदेशी युक्त बनाए रखना है। विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना है। स्थानीय उत्पादों का उपयोग एवं प्रोत्साहन करना होगा। साथी मोटे अनाज की और हम सभी को आकर्षित रहना है और रहने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा।

बैठक में विभिन्न कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया। जिला संयोजक रामावतार राम रवि, सह संयोजक जय किशन बिरूली, श्यामल दास, जिला संपर्क प्रमुख दिलीप साव, जिला युवा प्रमुख रोहित दास, जिला महिला प्रमुख शांति देवी, जिला विचार विभाग प्रमुख अजय गोप, जिला संघर्ष वाहिनी प्रमुख अनूप प्रसाद, जिला प्रचार प्रमुख केशव प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी राकेश पोद्दार, जिला कोषाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा एवं स्वावलंबी भारत अभियान के लिए संयोजक मिलन महतो तथा सह संयोजक अमित कुमार नाग को बनाया गया। बैठक में डॉ. अनिल राय, कौशल किशोर, प्रताप कटियार महतो, अजय गोप, कामेश्वर विश्वकर्मा, देव कुमार, प्रकाश महतो, राकेश पोद्दार, श्यामल दास, दिलीप साव, अनुप प्रसाद, दुर्योधन पान, अमित नाग, जय किशन बिरूली, रोहित दास, व्यास निषाद, यश खान्डाईत, अश्विनी खलको, पप्पू राय उपस्थित थे।

https://www.livehin

स्वदेशी आंदोलन के प्रथम शहीद बाबू गेनू को किया नमन

स्वदेशी आंदोलन के प्रथम शहीद गेनू बाबू के बलिदान दिवस पर उनकी स्मृति में पिंडोहरी, मखना के प्रांगण में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले गेनू बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विचार विभाग प्रमुख व प्राचार्य प्रोफेसर शर्वेश पांडेय ने कहा कि गेनू बाबू श्रमिक वर्ग से आते थे। उनके दिल में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना कोटि–कोटि कर भरी थी। वे लोगों को जागरूक करते हुए स्वदेशी सामान अपनाने एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन करते थे।

विशिष्ट अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक प्रोफेसर चंद्र प्रकाश राय, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह, लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री भरत थरड, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष एवं स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक आजाद यादव, प्रोफेसर हरि लाल, स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक पंकज तिवारी आदि ने गेनू बाबू के के बलिदान दिवस पर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के नवीन पदाधिकारियो की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि ने माला पहनाकर उन्हें अपने दायित्व का बोध कराते हुए पूर्ण रूप से संगठन के प्रति समर्पण की भावना से रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक सुशील सिंह और संचालन स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अजय तिवारी ने किया। ❑❑

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/mau/story-genu-babu-s-sacrifice-day-commemorated-by-swadeshi-jagran-manch-in-mau-201734111640054.html#google_vignette

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांत सम्मेलन

सचित्र झलक

हरियाणा

मेरठ

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 दिसंबर 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

बाबू गेनू बलिदान दिवस

(12 दिसंबर 2024)

सचित्र झलक

मऊ, उ.प्र.

वर्द्धमान, वेस्ट बंगाल

प्रयागराज

बलिया, उ.प्र.

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

ଉଡ଼ିସା

जमशेदपुर

राजयपुर, छत्तीसगढ़

सवाई माधोपुर, राज.

सीकर, राज.

सीतापुर, अवध

हरदोई, उ.प्र.

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती